जिला पंचायत मंदसौर/राजगढ़ (म.प्र.)

विषय- स्थानान्तरण श्रीमती दीप्ती तंवर, शिक्षाकर्मी वर्ग- 3 प्राथमिक विद्यालय बामनी केन्द्र पड़िया इस्तमुरार विकास खण्ड गरोठ जिला मंदसौर से राजगढ़।

आदेशानुसार लेख है कि विषयान्तर्गत प्रकरण में दीप्ती तंवर, शिक्षाकर्मी वर्ग-3, प्रा.वि. बामनी केन्द्र पड़िया इस्तमुरार विकास खण्ड गरोठ जिला मंदसौर में पदस्थ के विशेष प्रकरण के रूप में अपवादस्वरूप श्रीमती दीप्ती तंवर शिक्षाकर्मी वर्ग- 3 का स्थानान्तरण राजगढ़ जिले में किया जाता है। इनकी पदस्थापना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ द्वारा की जायेगी।

हस्ता/-
(डॉ. अरूणा गुप्ता)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी, 1998

क्र. एफ. 20-95-बाईस-पं.- 2.- मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 53 की उपधारा (2), धारा 70 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम, जो कि धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, बनाता है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मी (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 है.

(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994);

(ख) शिक्षा कर्मी के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची एक के कालम (5) में वर्णित प्राधिकारी;

(ग) "समिति" से अभिप्रेत है क्रमशः अनुसूची दो तथा चार में दिये गये अनुसार शिक्षा कर्मियों की, नियुक्ति या पदोन्नति के लिये गठित की गई चयन समिति;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) "पंचायत" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित की गई यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत;

(च) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "शिक्षा कर्मी" से अभिप्रेत है यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में पढ़ाने के लिये नियुक्त किया गया; और

(झ) "स्थायी समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित की गई

यथास्थिति जिला या जनपद पंचायत की शिक्षा समिति.

3. विस्तार तथा लागू होना.- ये नियम जनपद पंचायत या जिला पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों के लिये नियुक्त किये गये शिक्षा कर्मियों को लागू होंगे.

4. वर्गीकरण तथा वेतनमान.- शिक्षा कर्मियों का वर्गीकरण और उनके वेतनमान अनुसूची-एक में दिये गये अनुसार होंगे. सरकार या सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के सिवाय पदों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी.

5. चयन तथा भरती की पद्धति.- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् शिक्षा कर्मियों के संवर्ग की भरती निम्नलिखित पद्धति से की जायेगी, अर्थात्—

(क) सीधी भरती से चयन द्वारा.

(ख) अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार पदोन्नति द्वारा.

(2) सीधी भरती तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता, अनुसूची-तीन के कालम (4) तथा (5) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी.

(3) सीधी भरती तथा पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगी.

(4) शिक्षा कर्मियों की सीधी भरती के पद मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे.

(5) राज्य सरकार के नियमों के अनुसार महिलाओं, निःशक्त व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा ऐसे अन्य वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जायेंगे :

[1](परन्तु शिक्षाकर्मियों की भर्ती के लिए विज्ञापन सूचना की प्रति जिला रोजगार कार्यालय, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और महानिदेशक, पुनर्वास को भेजने के पश्चात् भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने पर, उक्त रिक्तियां अन्य प्रवर्गों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी।)

(6) शिक्षा कर्मियों के पद.-

(एक) अधिक संख्या में क्षेत्र में प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों में से कम से कम किसी एक समाचार पत्र में विज्ञापित किये जायेंगे;

(दो) स्थानीय रोजगार कार्यालय में अधिसूचित किये जायेंगे; और

(तीन) यथास्थिति संबंधित जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सूचना फलक पर प्रदर्शित किये जायेंगे.

(7) प्राप्त आवेदन की छानबीन करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्य वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार योग्यता सूची, पद के लिये विहित की गई अर्हता परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी. प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक प्रवर्ग में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से तिगुनी संख्या में योग्यता सूची के अनुसार परीक्षा या/तथा साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा. ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने कम से कम [1](एक शिक्षा सत्र जो 8 मास से कम का नहीं होगा) जनपद पंचायत या जिला पंचायत की शालाओं में कार्य किया हो, साक्षात्कार या परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा :

1. अधिसूचना क्र. एफ. 20-95-बाईस-पं-2, दिनांक 7 जुलाई, 99 द्वारा अंतःस्थापित/प्रतिस्थापित।

[1][परन्तु आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को, जिसके सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक या बराबर अंक हों, साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा।]

(8) चयन समिति यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सदस्यों से गठित की जायेगी. सामान्यतः चयन तथा नियुक्ति का कार्य ग्रीष्मावकाश के दौरान शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व किया जायेगा.

(9) (एक) यह समिति साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों का आकलन करेगी तथा निम्नलिखित रीति में अंक देगी—

[1][(क) विहित अर्हता परीक्षा के लिए वरीयता (वेटेज) देते समय अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट की गई अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के लिए 70 प्रतिशत अंक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को वरीयता (वेटेज), सैद्धांतिक, लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर ही दी जाएगी।

(ख) संबंधित जनपद पंचायत या जिला पंचायत के स्कूलों में शिक्षण के अनुभव के लिए 10 प्रतिशत अंक (एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष और उससे अधिक के अनुभव के लिए क्रमशः 3 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अंक जिसमें न्यूनतम आठ मास के शैक्षणिक सत्र की गणना एक वर्ष के अनुभव के रूप में की जाएगी और उसमें शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों, डी.पी.ई.पी. वैकल्पिक स्कूलों और औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों में शिक्षण का अनुभव भी सम्मिलित है।) राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत सहायता तथा मान्यता प्राप्त ग्रामीण स्कूलों में शिक्षण के अनुभव के लिए इसी प्रकार का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण स्कूलों में शिक्षण के अनुभव के प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता तथा मूल्यांकन पर सामान्य प्रशासन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।]

(ग) मौखिक साक्षात्कार के लिये [1][7] प्रतिशत अंक जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे.-

(एक) स्थानीय भाषा में बातचीत करने की दक्षता,

(दो) स्थानीय परिवेश की जानकारी,

(तीन) सामान्य ज्ञान,

(चार) प्रशिक्षण तथा शिक्षण के प्रति अभिरुचि,

(पांच) कोई अन्य परीक्षण जिसे चयन समिति उचित समझे.

[1][(घ) बी.एड./बी.टी.आई/डी.एड. प्रमाण-पत्र के लिए 8 प्रतिशत अंक, स्काउट और गाइड्स/एन.सी.सी. प्रमाण-पत्रों के लिए 2.5 प्रतिशत अंक और खेल के लिए (अंतर जिला या उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए) 2.5 प्रतिशत अंक]

(ङ) अंतिम चयन में, अन्य बातें समान होने की दशा में प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों को दी जायेगी, जिनके जनपद पंचायत या जिला पंचायत के विद्यालयों में शिक्षण का अनुभव है.

[1][(दो) प्रत्येक प्रवर्ग के लिए चयन सूची, योग्यता के क्रम में उपरोक्त आकलन के आधार पर तैयार की जाएगी और उसके अंतर्गत 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम, इनमें से जो भी अधिक हो, प्रतीक्षा सूची में होंगे जो कि नौ मास के लिए विधिमान्य होगी। नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की संख्या के बराबर एक एकीकृत चयन सूची इस क्रम में तैयार की जाएगी कि अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर होगा और अन्य नाम अवरोही क्रम में सर्वप्रथम सामान्य प्रवर्ग (अनारक्षित प्रवर्ग) में रिक्तियों की संख्या तक होंगे। यदि सामान्य प्रवर्गों की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी है तो उसकी नियुक्ति को आरक्षित प्रवर्ग के पद के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। इसके पश्चात् आरक्षित प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के नाम ऐसे प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग की कुल रिक्तियों की संख्या की समतुल्य चयन सूची की अतिरिक्त अभ्यर्थियों के 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम, इनमें से जो भी अधिक हो, उक्त सिद्धांतों के आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे जाएंगे।]

1. अधिसूचना क्र. एफ 20-95-सात-ब-2, दिनांक 7 जुलाई 99 द्वारा अंतःस्थापित/प्रतिस्थापित।

(10) चयन सूची से नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किये गये तथा यथास्थिति, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत द्वारा रखे गये रोस्टर के अनुसार की जायेगी.

6. अनुकम्पा नियुक्ति.- नियम 5 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार शिक्षा कर्मियों के ऐसी संख्या में अतिरिक्त पद मंजूर कर सकेगी जितने कि आवश्यक हों जिन पर पंचायत, कलेक्टर की सिफारिशों पर इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं नियमों या निर्देशों के अधीन अनुकम्पा के आधारों पर नियोजन के लिये पात्र व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगी.

7. परिवीक्षा.- शिक्षा कर्मियों के पद पर सीधी भरती से चयनित प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ में स्कूल विशेष के लिये तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा जिससे कि शिक्षा कर्मी पूरी परिवीक्षा कालावधि तक उसी स्कूल में कार्य कर सके. प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शिक्षा कर्मी के कार्य का आकलन किया जायेगा. तीन वर्ष के पश्चात् शिक्षाकर्मी को उनके कार्य, आचरण तथा कार्यपालन के आधार पर पंचायत के नियमित वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा. यदि शिक्षा कर्मी का कार्य समाधानप्रद नहीं पाया जाता है तो उसे एक से दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर बने रहने के लिये अनुज्ञात किया जा सकेगा। इसके पश्चात् पुनः बढ़ाई गई कालावधि के अंत में उसके कार्य का आकलन किया जायेगा.-यदि समाधानप्रद नहीं पाया जाये तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी.

परन्तु किसी भी दशा में परिवीक्षा कालावधि पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी. शिक्षा कर्मी को परिवीक्षा की कालावधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा उस पर प्रतीकार्य महंगाई भत्ता प्रदत्त किया जायेगा.

8. पदोन्नति.- (1) अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति पर नियुक्ति की जायेगी.

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण के क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित शिक्षा कर्मियों की पदोन्नति के लिये लागू होंगे.

9. अनुशासन व नियंत्रण.- शिक्षा कर्मी यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे. दीर्घ शास्ति के लिये यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति तथा लघु शास्ति के लिये पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्रमशः अनुशासनिक अधिकारी होंगे.

10. सेवा समाप्ति.- ऐसे शिक्षा कर्मी की जो स्थायी सेवा में न हो, सेवाएं या तो शिक्षा कर्मी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी का शिक्षा कर्मी को लिखित में एक मास की सूचना देकर या एक मास का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जाने के दायित्वाधीन होंगी.

11. सामान्य सेवा शर्तें- शिक्षा कर्मियों की ऊपर वर्णित शर्तों से भिन्न, सेवा की शर्तें यथास्थिति, जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान ही होंगी.

12. अपील.- इन नियमों के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जायेगी.

13. निर्वचन.- इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

14. निरसन और व्यावृत्ति.- इन नियमों के आरम्भ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त, तत्स्थानी समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी.

अनुसूची एक

[देखिए नियम 2 (ख)]

अनु. क्र. (1)	शिक्षा कर्मी वर्ग (2)	पदों की संख्या (3)	वेतनमान (4)	नियुक्ति प्राधिकारी (5)
1.	वर्ग-1	.....	1200-40-2000	जिला पंचायत
2.	वर्ग-2	.....	1000-30-1600	जिला पंचायत
3.	वर्ग-3	.....	800-20-1200	जनपद पंचायत

*टीप.- (1) प्रत्येक शाला के लिये शिक्षा कर्मियों की विभिन्न श्रेणी के लिये पदों की संख्या का निर्धारण यथास्थिति संबंधित उप संचालक शिक्षा या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा प्रमाणित किया जायेगा.

(2) सरकार सम्यक् प्रमाणित प्रस्ताव प्राप्त होने पर, समय-समय पर प्रत्येक पंचायत के लिये शिक्षा कर्मियों के पदों की संख्या अनुमोदित करेगी.

अनुसूची दो

[देखिए नियम 2 (ग) तथा नियम 5]

अनु. क्र. (1)	शिक्षा कर्मी वर्ग (2)	न्यूनतम आयु (3)	*अधिकतम आयु (4)	शैक्षणिक योग्यता (5)	चयन समिति के सदस्य (6)
1	वर्ग-1	21	[1][33]	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष	1. सभापति, जिला पंचायत की [2][सामान्य प्रशासन समिति] 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत. 3. यथास्थिति उप संचालक, शिक्षा या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (सदस्य-सचिव) 4. [2][सामान्य प्रशासन समिति] द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ जिनमें से एक महिला हो, तथा 5. [2][सामान्य प्रशासन समिति] के समस्त सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो. यदि स्थायी समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य उपलब्ध नहीं हों तो ऐसे वही सदस्य सामान्य सभा में नामनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे.
2	वर्ग-2	21	[1][33]	संबंधित विषय समूह में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि	—सदैव—
3	वर्ग-3	18	[1][33]	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण	1. सभापति, [2][सामान्य प्रशासन समिति], जनपद पंचायत 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत 3. विकास खंड शिक्षा अधिकारी (सदस्य-सचिव)

1. अधिसूचना क्र. एफ 20-95-बाईस-पं-2, दिनांक 13-4-98 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्र. एफ 20-95-बाईस-पं-2, दिनांक 7 जुलाई, 99 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					4. जनपद पंचायत की [1][सामान्य प्रशास समिति] द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विष विशेषज्ञ जिनमें से एक महिला हो, त 5. [1][सामान्य प्रशासन समिति] के समस सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा व वर्ग का हो. यदि स्थायी समिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य उपलब्ध नहीं हों तो वही सदस्य सामान्य सभा नामनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे.

*टीप.- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी.

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिये अन्य सभी छूटों के लिये अतिरिक्त उच्चतर आयु सीमा में दस वर्ष की छूट रहेगी.

(3) जिन अभ्यर्थियों ने संबंधित जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के पर्यवेक्षण के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष तक कार्य किया है उन्हें उच्चतर आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जा सकेगी.

अनुसूची-तीन

[देखिए नियम 5 (2)]

अनु. क्र. (1)	शिक्षा कर्मी वर्ग (2)	*पदो की संख्या (3)	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता: सीधी भरती द्वारा (4)	पदोन्नति द्वारा (5)
1.	वर्ग-1	.....	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2.	वर्ग-2	.....	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
3.	वर्ग-3	.....	100 प्रतिशत	—

*टीप.- (1) शालाओं में शिक्षा कर्मियों के विभिन्न वर्गों के सीधी भरती तथा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का आंकलन तथा प्रमाणीकरण यथास्थिति उप संचालक, शिक्षा या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा किया जायेगा.

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने से प्रथम सात वर्षों तक वर्ग- 1, 2 तथा 3 के शिक्षा कर्मियों के सभी पद सीधी भरती से भरे जायेंगे. इसके पश्चात् उक्त अनुसूची के अनुसार पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी :

परन्तु किसी भी समय पदोन्नति के पद पचास प्रतिशत से अधिक नहीं रखे जायेंगे तथा पदोन्नति के पदों पर नियमों के प्रभावशील होने के सात वर्षों के पश्चात् सीधी भरती नहीं की जा सकेगी।

1 अधिसूचना क्र. एफ 20-95-बाईस-पं-2, दिनांक 7-7-1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुसूची चार

[देखिए नियम 5 (1) (ख) तथा नियम 8]

अनुक्र.	पदनाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पद जिस पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति के लिये अर्हता तथा अनुभव	पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शिक्षा कर्मी वर्ग-2	शिक्षा कर्मी वर्ग-1	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा शिक्षक पद पर कार्य से कम 7 वर्ष का अनुभव	1. सभापति जिला पंचायत की स्थायी शिक्षा समिति. 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत. 3. यथास्थिति उप संचालक, शिक्षा या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास. 4. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग. 5. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी, यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो.
2.	शिक्षा कर्मी वर्ग-3	शिक्षा कर्मी वर्ग-2	स्नातक उपाधि तथा धारित पद पर 7 वर्ष पढ़ाने का अनुभव.	

—सदैव—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश मिश्र,
उपसचिव

[म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1-1-1998 को पृष्ठ क्र. 1 पर प्रकाशित]

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल, 1998

क्र.एफ. 20-95- बाईस- पं.- 2.- मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 53 की उपधारा (2), धारा 70 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मी (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 में जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 5 के उपनियम (9) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (ख) में, शब्द "समतुल्य ग्रामीण शालाओं में" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत सहायता तथा मान्यता प्राप्त ग्रामीण शालाओं में" स्थापित किए जाएं.

(2) अनुसूची दो में,

(क) कालम (4) में अनुक्रमांक 1 के सामने अंक "35" के स्थान पर अंक "33" स्थापित किया जाए.

(ख) कालम (4) में अनुक्रमांक 2 के सामने अंक "32" के स्थान पर अंक "33" स्थापित किया जाए.

(ग) कालम (4) में अनुक्रमांक 3 के सामने अंक "30" के स्थान पर अंक "33" स्थापित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार,
सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई, 1998

क्र. एफ-20-95-बाईस-पं. 2.- उन नियमों का जिनमें राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा धारा 70 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश शिक्षा कर्मी (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करना प्रस्तावित करती है, निम्न लिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे सभी व्यक्तियों को जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से सात दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से उक्त विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) उद्देशिका में, शब्द तथा अंक "धारा 53 की उपधारा (2)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)" स्थापित किया जाए.

(2) नियम 2 के खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए:

"(ञ) "अनुसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र."

(3) नियम 5 के उप नियम (9) के खण्ड (दो) में, शब्द तथा अंक "10 प्रतिशत नाम प्रतीक्षा-सूची में होंगे जो छह मास तक विधिमान्य होगी" के स्थान पर शब्द तथा अंक "5 नाम या 20 प्रतिशत नाम जो भी अधिक हो प्रतीक्षा-सूची में होंगे जो पाँच मास तक विधिमान्य होगी" स्थापित किए जाएं.

(4) अनुसूची दो में,

(क) अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (6) में शब्द "5. सभापति" के अंत में जोड़ा जाए.

(5) (69)

4

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462003

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 28-6-07

क्रमांक एफ 1–4/07/बीस–1 : राज्य शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की पंचायत राज एवं नगरीय निकाय को अंतरित शालाओं में कार्यरत संविदा शाला शिक्षक, शिक्षाकर्मी एवं गुरूजी आदि के भेदों को समाप्त कर उनके नियमितिकरण की प्रकिया निर्धारित करने के लिए श्री डी0 पी0 दुबे (सेवानिवृत्त आई0ए0एस0) की अध्यक्षता में एकल समिति का गठन म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक/3095/ 4473/05/ 1/3, भोपाल, दिनांक 19.12.2005 द्वारा किया गया था।

2. श्री डी. पी. दुबे समिति की अनुशंसाओं पर विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैं:–

2.1 पंचायतों एवं नगरीय निकायों में कार्यरत शिक्षाकर्मी संवर्ग समाप्त करते हुए उनके स्थान पर अध्यापक संवर्ग का गठन किया जाए।

2.2 अध्यापक संवर्ग में सम्मिलित पद एवं उनके वेतनमान निम्नानुसार होंगे:–

1.	वरिष्ठ अध्यापक	–	रु. 5000–175–8500
2.	अध्यापक	–	रु. 4000–125–6500
3.	सहायक अध्यापक	–	रु. 3000–100–5000

2.3 अध्यापक संवर्ग का गठन दिनांक 01.04.2007 से किया जाए।

(6) (70)

5

2.4 शिक्षाकर्मी –

(क) मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1997 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1998 के तहत् नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग–1, 2 एवं 3 का अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर संविलियन किया जाए । शिक्षाकर्मी वर्ग–1 को वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षाकर्मी वर्ग–2 को अध्यापक व शिक्षाकर्मी वर्ग–3 को सहायक अध्यापक के पद व वेतनमान में संविलियन किया जाए। अध्यापक संवर्ग में संविलियन करते समय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए । संविलियन करते समय आरक्षित संवर्ग के शिक्षाकर्मियों को, जिनकी नियुक्ति अनारक्षित संवर्ग के अंतर्गत हुई है को अनारक्षित संवर्ग में एवं आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त शिक्षाकर्मियों को आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के रोस्टर में रखा जाए। अध्यापक संवर्ग में संविलियन किए गए शिक्षाकर्मियों की आपसी वरिष्ठता वही होगी, जो शिक्षाकर्मी संवर्ग में थी ।

(ख) अध्यापक संवर्ग में वेतन निर्धारण करते समय शिक्षाकर्मी संवर्ग में पूर्ण किये गये प्रत्येक तीन वर्ष के पूर्ण कालखण्ड के लिए अध्यापक संवर्ग में एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए । तीन वर्ष से कम कार्यकाल के लिए वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी । निर्धारित किए गए वेतन पर दिनांक 01.04.2007 से 20 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय होगा। इस तिथि के बाद जब–जब म.प्र. शासन के कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते में वृद्धि होगी तदनुसार अध्यापक संवर्ग को भी मंहगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा । ऐसे शिक्षाकर्मी जिन्हें अध्यापक संवर्ग के नये वेतनमान में पुराने वेतनमान की तुलना में कुल प्राप्त परिलब्धियों (वेतन वृद्धि एवं उस पर देय 20 प्रतिशत मंहगाई भत्ते सहित) का अंतर रु. 750/– से कम है तो उस शिक्षाकर्मी को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का अधिभार देकर वेतन निर्धारण किया जाए ।

(7) (71)

(ग) ऐसे शिक्षाकर्मी जिन्होंने एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण (बी.एड./डी.एड.) की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त नहीं की है उन्हें निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने के उपरान्त ही अध्यापक संवर्ग में अगली वेतनवृद्धियां स्वीकृत की जाएं। ऐसे मामलों में शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि करने पर छूटी हुई वेतनवृद्धियां जारी की जाए किन्तु एरियर्स की पात्रता नहीं होगी। ऐसे शिक्षाकर्मियों को स्वयं के व्यय पर शिक्षण–प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करना होगी, जिसके लिए उन्हें एक बार सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए।

(घ) शिक्षाकर्मियों का उपरोक्तानुसार अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक 01.04.2007 से किया जाएगा । इनके अध्यापन कार्यकाल की गणना दिनांक 01.04.2007 की स्थिति में की जावेगी । संविलियन के उपरांत उन्हें कंडिका 2.2 में उल्लेखित वेतनमान प्राप्त होगा।

2.5 संविदा शाला शिक्षक –

(क) संविदा शाला शिक्षकों को तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति काल पूर्ण करने के उपरान्त अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता पर विचार एक छानबीन समिति द्वारा किया जाए। संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्त तभी किया जाए जब संविदा काल में उनका कार्य विभाग द्वारा निर्धारित वस्तुपरक मापदण्डों पर संतोषजनक रहा हो, तथा उनके द्वारा एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त कर ली गई हो । अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के समय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए। नियुक्ति करते समय आरक्षित संवर्ग के संविदा शाला शिक्षकों को, जिनकी नियुक्ति अनारक्षित संवर्ग के अंतर्गत हुई है को अनारक्षित संवर्ग में एवं आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों को आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के रोस्टर में रखा जाए। छानबीन समिति एवं वस्तुपरक मूल्यांकन के मापदंड हेतु पृथक से आदेश जारी किये जा रहे है।

(ख) जिन संविदा शाला शिक्षकों का संविदा काल में कार्य उक्तानुसार निर्धारित वस्तुपरक मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के आधार पर नये संवर्ग में प्रवेश नहीं दिया जाता है उनकी संविदा का आगे नवीनीकरण नहीं किया जाए ।

(ग) जिन संविदा शाला शिक्षकों का संविदा काल में कार्य उक्तानुसार निर्धारित वस्तुपरक मापदण्डों के अनुरूप रहा है परन्तु केवल निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त नहीं होने के कारण उनकी नये संवर्ग में नियुक्ति नहीं हो पायी हो उनकी संविदा अवधि का आगामी तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाए तथा उन्हें स्वयं के व्यय पर शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। ऐसे संविदा शाला शिक्षकों को इस हेतु एक बार सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने पर ही पुनः उनकी अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता के संबंध में छानबीन समिति द्वारा विचार किया जाए और योग्य पाए जाने पर उन्हें अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाए। ऐसे संविदा शाला शिक्षक जो दूसरी संविदा अवधि के उपरान्त भी अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते है या निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि की अर्हता प्राप्त नहीं करते है, उनकी संविदा नियुक्ति का आगे नवीनीकरण नहीं किया जाए ।

(घ) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 को वरिष्ठ अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 को अध्यापक एवं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 को सहायक अध्यापक के पद पर अध्यापक संवर्ग के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाए।

(ङ) संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग के समान अनुग्रह राशि (Ex-gratia) दी जाए ।

(घ) वर्ष 2001 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका क्रमांक–21473/2004 एवं 4659/2005 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.04.2005 द्वारा स्थगन है। अतः अध्यापक संवर्ग में इनकी नियुक्ति की कार्रवाई अभी स्थगित रहेगी । इस संबंध में राज्य शासन द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्राप्त होने पर उक्त निर्णय के अध्यधीन पृथक से आदेश जारी किए जाऐंगे ।

(छ) वर्ष 2003 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की संविदा नवीनीकरण के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में आई0ए0 दायर कर इस संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश चाहे गये है। अतः अध्यापक संवर्ग में इनकी नियुक्ति की कार्रवाई अभी स्थगित रहेगी । इस संबंध में राज्य शासन द्वारा मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त होने पर पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे ।

(ज) संविदा शाला शिक्षक भर्ती की वर्तमान व्यवस्था निरंतर जारी रखी जाए। संविदाकाल के पूर्ण होने के उपरांत संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता पर विचार करने हेतु गठित छानबीन समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर उपरोक्त कंडिकाओं अनुसार अध्यापक संवर्ग के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाए।

26 गुरूजी –

ऐसी ई.जी.एस. शालाएं जिन्हें प्राथमिक शाला में प्रौन्नत नहीं किया गया है एवं जिनके गुरूजियों को वर्तमान में एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, ऐसे गुरूजियों को देय मानदेय में रु. 750/– प्रतिमाह की वृद्धि की जाए।

राज्य शासन के उपरोक्त निर्णय के अनुसार शिक्षाकर्मियों के अध्यापक संवर्ग में संविलियन व वेतन निर्धारण करने की कार्यवाही स्थानीय निकायों द्वारा निम्नानुसार तत्काल कर ली जाए:--

शिक्षाकर्मी श्रेणी	प्राधिकारी जिसके द्वारा संविलियन के आदेश जारी किए जाएंगे व वेतन निर्धारण किया जाएगा
शिक्षाकर्मी वर्ग–1 एवं शिक्षाकर्मी वर्ग–2 का क्रमशः वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक के पदों पर संविलियन	संबंधित जिला पंचायत अथवा नगरीय निकाय
शिक्षाकर्मी वर्ग–3 का सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन	संबंधित जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय

राज्य शासन के संबंधित विभागों द्वारा अध्यापक स्तर के [illegible] एवं संट [illegible] नियमों को बनाने की कार्यवाही की जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(के. सी. पंत)
अवर सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 28-6-07

पृ0क्रमांक :
प्रतिलिपि:--

1. सचिव, मुख्य मंत्रीजी, म0प्र0 शासन ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन ।
3. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, म0प्र0 शासन ।
4. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, म0प्र0 शासन ।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
6. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 शासन [illegible]

7. प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, म0प्र0 शासन ।
8. सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म0प्र0 शासन ।
9. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म0प्र0 शासन ।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0 ।
11. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म0प्र0 ।
12. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल, म0प्र0 ।
13. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग ।
14. समस्त, कलेक्टर,
15. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
16. समस्त, आयुक्त, नगर निगम,
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
18. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
19. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,
20. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत,
21. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

मध्यप्रदेश ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

(12)

(50)

(1)

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-103-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 556] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 सितम्बर 2008—भाद्र 20, शक 1930

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्र. एफ-1-3-2008-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' दिनांक 13 अगस्त, 2008 को पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 है.

(2) ये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक, सन् 1994);

(ख) अध्यापक के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कालम (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) ''अर्हता'' से अभिप्रेत हैं, अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट अध्यापक संवर्ग की अर्हताएं;

(ङ) ''पंचायत'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन गठित की गयी यथास्थिति, कोई जिला पंचायत या जनपद पंचायत;

(च) ''अध्यापक संवर्ग'' से अभिप्रेत है, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में अध्यापन के लिए नियोजित/संविलियन किया गया व्यक्ति;

(छ) "शिक्षाकर्मी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश [illegible] शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1997 के यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद [illegible] के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(ज) "संविदा शाला शिक्षक" से अभिप्रेत [illegible] संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की नियम, 2005 के अधीन यथास्थिति, जिला [illegible] जनपद पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में [illegible] के लिये नियोजित/नियुक्त किया गया [illegible];

(झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची; और

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. विस्तार तथा लागू होना.—ये नियम, यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन समस्त स्कूलों के नियोजित/संविलयन किए गए प्रत्येक अध्यापक संवर्ग को लागू होंगे.

4. वर्गीकरण तथा वेतनमान.—अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण और वेतनमान ऐसे होंगे जैसा कि इन नियमों से संलग्न अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किया जाए. सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या इस निमित्त राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, परिवर्तित नहीं की जाएगी.

5. चयन तथा नियुक्ति का तरीका.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् अध्यापक संवर्ग में भर्ती निम्नलिखित तरीके से की जाएगी, अर्थात्:—

(1) मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षाकर्मी के संविलयन द्वारा;

स्पष्टीकरण.—(एक) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रेड)-1 का संविलयन वरिष्ठ अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा.

(दो) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रेड)-2 का संविलयन अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा.

(तीन) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रेड)-3 का संविलयन सहायक अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा.

(चार) अध्यापक संवर्ग में प्रत्येक व्यक्ति का संविलयन दिनांक 1-4-2007 की स्थिति में किया जाएगा, जबकि अध्यापक संवर्ग में उनके वेतन निर्धारण करते समय शिक्षाकर्मी के रूप में तीन वर्ष की निरंतर सेवा करने वाले व्यक्ति को अध्यापक संवर्ग में एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा. आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 1-4-08 से प्रभावी होगी.

(2) संविदा शाला शिक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर नियुक्त किया जाएगा:—

(क) ऐसे संविदा शाला शिक्षक को जिसने तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति की कालावधि पूर्ण कर ली है तथा अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु पात्रता पर विचार करने हेतु गठित छानबीन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के [illegible] पात्र पाये जाने पर, अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाएगा.

(ख) क्रमशः संविदा शाला शिक्षक श्रेणी—1 को वरिष्ठ अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी—2 को अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी—3 को सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापक संवर्ग के वेतनमान के न्यूनतम पर नियुक्त किया जाएगा. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख एक वर्ष की सेवा के पूर्ण करने के पश्चात होगी.

(ग) अध्यापक संवर्ग में ऐसे संविदा शाला शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जिन्होंने अनुसूची—दो के कॉलम (3) में विहित शैक्षणिक एवं शिक्षण/प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त कर ली हो.

(घ) अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए छानबीन समिति के नाम से एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत — अध्यक्ष

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (संबंधित) — सदस्य

(3) जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण — सदस्य सचिव

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग का एक अधिकारी — सदस्य

(3) नियुक्ति/तबितयन करते समय मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक एफ 6 1 2002 आ.प.-एक, दिनांक 19-9-2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा और समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में कार्रवाई की जाएगी.

6. पदोन्नति.—अनुसूची—चार में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति पर नियुक्ति की जाएगी; वेतन निर्धारण इस निमित्त बनाए गए पंचायत विभाग के नियमों के अनुसार किया जाएगा.

7. अपील.—इन नियमों के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अधिनियम में यथा उल्लिखित संबंधित अपील प्राधिकारी को अपील करेगा.

8. अन्य शर्तें.—(क) इन नियमों के अधीन नियोजित कोई व्यक्ति जिला पंचायत या जनपद पंचायत के प्रशासकीय तथा अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा. अध्यापक संवर्ग के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे:—

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग (2)	अनुशासनात्मक प्राधिकारी (3)	अपीलीय प्राधिकारी (4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर
2	अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर
3	सहायक अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर

टिप्पण.—कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करेगा.

(ख) इन नियमों के अधीन नियोजित या संविलयन किया गया कोई व्यक्ति, स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षकों के अवकाश का हकदार होगा.

(ग) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई भी व्यक्ति मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 द्वारा शासित

(घ) अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्तियों की अधिवार्षिकी की आयु 62 वर्ष होगी.

(ङ) इन नियमों के अधीन नियोजित व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति के लिए वही शर्तें होंगी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अ की जाए.

(च) इन नियमों के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अध्यापक संवर्ग के लिए राज्य सरक समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार देय होंगे.

9. राज्य सरकार की शक्ति.—इन नियमों के अधीन विहित करने की शक्ति का प्रयोग राज्य राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करके किया जाएगा.

10. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किय जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा.

11. निरसन और व्यावृत्ति.—मध्यप्रदेश [illegible] (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1997 एतद्द्वारा निरसित किए

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गयी कोई कार्रवाई के संबंध में यह समझा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश है या की गई कार्रवाई है

अनुसूची—एक

[नियम-2(ख) तथा नियम-4]

अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण तथा वेतनमान

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण (2)	वेतनमान (3)	नियुक्ति प्राधिकारी (4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	5000—175—8500	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
2	अध्यापक	4000—125—6500	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
3	सहायक अध्यापक	3000—100—5000	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

अनुसूची—दो

[नियम-2(घ)]

अध्यापक संवर्ग के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अर्हताएं

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण (2)	शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अर्हता (3)	अभ्युक्तियां (4)
1.	वरिष्ठ अध्यापक	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड./बी. एड. (विशेष शिक्षा).	संस्कृत पाठशाला के वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी में

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अध्यापक	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा)/बी.टी.सी./डी.एड./डी.एस.ई.	संस्कृत पाठशाला के अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि होगी.
3	सहायक अध्यापक	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा या समकक्ष एवं बी.टी.सी./डी.एड./डी.एस.ई.	(1) संस्कृत पाठशाला के सहायक अध्यापक (संस्कृत) के लिए संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से संस्कृत में उत्तर मध्यमा न्यूनतम अर्हता होगी. (2) सहायक अध्यापक (संगीत/तबला शिक्षक) के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत प्रमाण-पत्र में न्यूनतम अर्हता होगी. (3) सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) के लिए उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा का प्रमाण-पत्र न्यूनतम अर्हता होगी.

टिप्पण.—1. अध्यापक संवर्ग के पद मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षकों (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1997 अधीन नियुक्त किए गए शिक्षकों के संविलयन से भरे जाएंगे.

2. मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के अधीन नियुक्त किये गये संविदा शाला शिक्षक तीन वर्ष की संविदा कालावधि पूर्ण होने के पश्चात् अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किए जाएंगे.

3. अध्यापक संवर्ग में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी.

अनुसूची—तीन

[नियम-5 एवं 6 देखिए]

अध्यापक संवर्ग के पदों का विवरण

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग (2)	पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता (3)
1	वरिष्ठ अध्यापक	50 प्रतिशत
2	अध्यापक	50 प्रतिशत

टिप्पण.—अनुक्रमांक 1 तथा 2 में उल्लिखित पद सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरे जाएंगे. इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सीधी भर्ती संवर्ग के अधीन उपलब्ध पद की कुल संख्या में से:—

1. 50 प्रतिशत पद संविदा शाला शिक्षक के श्रेणी (ग्रेड)-1 तथा श्रेणी (ग्रेड)-2 की सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए जाएंगे.

2. शेष 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ अध्यापक तथा अध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे.

(55) (17)

(6)

अनुसूची—चार

[नियम 2(घ) तथा नियम 6]

अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति

अनुक्रमांक (1)	पदनाम जिससे पदोन्नति की जाना है (2)	पदनाम जिस पर पदोन्नति की जाना है (3)	पदोन्नति के लिए अर्हता तथा अनुभव (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य (5)
1	अध्यापक	वरिष्ठ अध्यापक	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण उपाधि / पत्रोपाधि (डिप्लोमा) तथा धारित पद पर न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो.	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत—अध्यक्ष. 2. जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आदिम जाति/जिला संयोजक, आदिम कल्याण विभाग—सदस्य. 3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्दिष्ट प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—सदस्य. 4. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से एक अधिकारी—सदस्य.
2	सहायक अध्यापक	अध्यापक	संबंधित विषय में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण उपाधि / पत्रोपाधि (डिप्लोमा) तथा धारित पद पर न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो.	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत—अध्यक्ष. 2. जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आदिम जाति/ जिला संयोजक, आदिम कल्याण विभाग—सदस्य. 3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा नामित प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—सदस्य. 4. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से एक अधिकारी—सदस्य.

टिप्पण.—1. अध्यापक संवर्ग में शिक्षाकर्मियों के संविलयन के पश्चात् शिक्षाकर्मी के रूप में उनके द्वारा की गई सेवा की गणना केवल पदोन्नति/क्रमोन्नति/वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु की जाएगी.

अनुसूची—पांच

अध्यापक संवर्ग के पदों की संख्या का निर्धारण

1. जितनी संख्या में, शिक्षाकर्मियों का संविलियन अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर किया जाएगा, उतनी ही संख्या में अध्यापक संवर्ग में सृजित किए गए समझे जाएंगे.

2. जितनी संख्या में, संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति अध्यापक संवर्ग सुसंगत पद पर की जाएगी, उतनी ही संख्या में अध्यापक संवर्ग में सृजित किए गए समझे जाएंगे एवं उतनी संख्या में संविदा शाला शिक्षक संवर्ग से पद समाप्त किए गए समझे जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्र. एफ-1-3-2008-बाईस-पं.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-बाईस-पं-2-08, दिनांक 11 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान पंजीयन डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 562] भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर 2008—भाद्र 26, शक 1930

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्र. 39-1692-08-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 433 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

(ख) "अध्यापक संवर्ग" के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 58 के अधीन तथा नगरपालिका तथा नगर पंचायत की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 94 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ग) "अर्हता" से अभिप्रेत है, अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट अध्यापक संवर्ग की अर्हताएं;

(घ) "नगरीय निकाय" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन गठित किया गया कोई नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन गठित की गई कोई नगरपालिका या नगर पंचायत;

(च) "अध्यापक संवर्ग" से अभिप्रेत है, नगरीय निकाय द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में अध्यापन के लिये नियोजित/संविलयन किया गया व्यक्ति;

(छ) "शिक्षाकर्मी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1998 के अधीन नगरीय निकाय द्वारा अध्यापन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(ज) "संविदा शाला शिक्षक" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के अधीन नगरीय निकाय द्वारा नियोजित/नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची; और

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. विस्तार तथा लागू होना.—ये नियम, नगरीय निकाय द्वारा उनके नियंत्रणाधीन समस्त स्कूलों के लिए नियुक्त/संविलयन किए गए प्रत्येक अध्यापक संवर्ग को लागू होंगे.

4. **वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण और वेतनमान ऐसा होगा जैसा कि इन नियमों से संलग्न अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किया जाए. सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या इस निमित्त राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय परिवर्तित नहीं की जाएगी.

5. चयन तथा नियुक्ति का तरीका.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् अध्यापक संवर्ग में भर्ती निम्नलिखित तरीके के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:—

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1998 के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षाकर्मियों के संविलयन द्वारा;

स्पष्टीकरण.—(एक) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रेड)—1 का संविलयन वरिष्ठ अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा.

(दो) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रेड)—2 का संविलयन अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा,

(तीन) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रेड)—3 का संविलयन सहायक अध्यापक के पद तथा वेतनमान में किया जाएगा.

(चार) अध्यापक संवर्ग में प्रत्येक व्यक्ति का संविलयन दिनांक 1 अप्रैल 2007 की स्थिति में किया जाएगा, जबकि अध्यापक संवर्ग में उनके वेतन निर्धारण करते समय शिक्षाकर्मी के रूप में तीन वर्ष की निरंतर सेवा करने वाले व्यक्ति को अध्यापक संवर्ग में एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा. आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होगी.

(2) संविदा शाला शिक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर नियुक्त किया जाएगा:—

(एक) ऐसे संविदा शाला शिक्षक को जिसने तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति कालावधि पूर्ण कर ली है तथा अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु पात्रता पर विचार करने हेतु गठित छानबीन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र पाये जाने पर, अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाएगा.

(दो) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी (ग्रेड)—1 को वरिष्ठ अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी (ग्रेड)—2 को अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी (ग्रेड)—3 को क्रमशः सहायक अध्यापक के रूप में, अध्यापक संवर्ग के वेतनमान के न्यूनतम पर नियुक्त किया जाएगा. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख एक वर्ष की सेवा के पूर्ण करने के पश्चात् होगी.

(तीन) अध्यापक संवर्ग में ऐसे संविदा शाला शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जिन्होंने अनुसूची—दो के कॉलम (3) में विहित शैक्षणिक एवं शिक्षण/प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त कर ली हो.

(चार) अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए छानबीन समिति के नाम से एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

(1)	कलक्टर का प्रतिनिधि (नगरपालिका/नगर पंचायत के लिए) आयुक्त, नगरपालिक निगम (नगरपालिक निगम के लिए)	—	अध्यक्ष
(2)	(1) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत (2) जिला शिक्षा अधिकारी (नगरपालिक निगम के लिये)	—	सदस्य-सचिव
(3)	जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त (नगरपालिका/नगर पंचायत के लिए)/ कलक्टर का प्रतिनिधि (नगरपालिक निगम के लिए)	—	सदस्य
(4)	अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग से एक अधिकारी	—	सदस्य

(3) नियुक्ति/संविलयन करते समय मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक एफ-6-1-2002-आ.प्र.-एक, दिनांक 19 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा और समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में कार्रवाई की जाएगी.

6. **पदोन्नति.**—पदोन्नति पर नियुक्ति अनुसूची—चार में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जाएगी. वेतन निर्धारण इस निमित्त बनाए गए नगरीय निकाय के नियमों के अनुसार किया जाएगा.

7. **अपील.**—इन नियमों के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अधिनियम में यथाउल्लिखित संबंधित अपील प्राधिकारी को अपील करेगा.

8. अन्य शर्तें.—(क) इन नियमों के अधीन नियोजित कोई व्यक्ति, नगरीय निकाय के प्रशासकीय तथा अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा. अध्यापक संवर्ग के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे:—

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग (2)	अनुशासनात्मक प्राधिकारी (3)	अपीलीय प्राधिकारी (4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर
2	अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर
3	सहायक अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर

टिप्पण.—कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करेगा.

(ख) इन नियमों के अधीन नियुक्त या संविलयन किया गया कोई व्यक्ति, स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षकों के समान अवकाश का हकदार होगा.

(ग) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई भी व्यक्ति, नगरीय निकाय नियमों द्वारा शासित होगा.

(घ) अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्तियों की अधिवार्षिकी की आयु 62 वर्ष होगी.

(ङ) इन नियमों के अधीन नियोजित व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति के लिए वही शर्तें होंगी जो राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित की जाएं.

(च) इन नियमों के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अध्यापक संवर्ग के लिये राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर अधिसूचित किये गये अनुसार देय होंगे.

9. राज्य सरकार की विहित करने की शक्ति.—इन नियमों के अधीन विहित करने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश जारी करके किया जायेगा.

10. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा.

11. निरसन और व्यावृत्ति.—मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1993 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई के संबंध में यह समझा जावेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश है या की गई कार्रवाई है.

अनुसूची—एक

[नियम-2(ख) तथा नियम-4]

अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण तथा वेतनमान

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण (2)	वेतनमान (3)	नियुक्ति प्राधिकारी (4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	5000—175—8500	नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार
2	अध्यापक	4000—125—6500	नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार
3	सहायक अध्यापक	3000—100—5000	नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार

अनुसूची—दो

[नियम-2(ब)]

अध्यापक संवर्ग के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी अर्हताएं

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण (2)	शैक्षणिक एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी अर्हता (3)	अभ्युक्तियां (4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड./बी. एड. (विशेष शिक्षा).	संस्कृत पाठशाला के वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यताप्राप्त प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि होगी.
2	अध्यापक	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा)/ बी.टी.सी./डी.एड./डी.एस.ई.	संस्कृत पाठशाला के अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि होगी.
3	सहायक अध्यापक	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा या समकक्ष एवं बी.टी.सी./डी.एड./ डी.एस.ई.	(1) संस्कृत पाठशाला के सहायक अध्यापक (संस्कृत) के लिए संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यताप्राप्त संस्था/ बोर्ड से संस्कृत में उत्तर मध्यमा न्यूनतम अर्हता होगी. (2) सहायक अध्यापक (संगीत/तबला शिक्षक) के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत प्रमाण-पत्र न्यूनतम अर्हता होगी. (3) सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) के लिए उ. मा. प्रमाण-पत्र परीक्षा के अतिरिक्त किसी मान्यताप्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा का प्रमाण-पत्र न्यूनतम अर्हता होगी.

टिप्पण.—1. अध्यापक संवर्ग के पद मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1998 के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षाकर्मियों के संविलियन से भरे जाएँगे.

2. मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के अधीन नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के तीन वर्ष की संविदा कालावधि पूर्ण होने के पश्चात् अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किए जाएंगे.

3. अध्यापक संवर्ग में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी.

अनुसूची—तीन

(नियम-5 एवं 6 देखिए)

अध्यापक संवर्ग के पदों के ब्यौरे (विवरण)

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग (2)	पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता (3)
1	वरिष्ठ अध्यापक	50 प्रतिशत
2	अध्यापक	50 प्रतिशत

टिप्पण.—अनुक्रमांक 1 तथा 2 में उल्लिखित पद सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरे जाएंगे. इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सीधी भर्ती संवर्ग के अधीन उपलब्ध पद की कुल संख्या में से. –

1. 50 प्रतिशत पद संविदा शाला शिक्षक के श्रेणी (ग्रेड)-1 तथा श्रेणी (ग्रेड)-2 की सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए जाएंगे.
2. शेष 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ अध्यापक तथा अध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे.

अनुसूची—चार

[नियम-2(घ) तथा नियम 6]

अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति

अनु-क्रमांक (1)	पदनाम जिससे पदोन्नति की जाना है (2)	पदनाम जिस पर पदोन्नति की जाना है (3)	पदोन्नति के लिए अर्हता तथा अनुभव (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य (5)
1	अध्यापक	वरिष्ठ अध्यापक	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी उपाधि/पत्रोपाधि तथा धारित पद पर न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव.	1. नियुक्ति प्राधिकारी नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार—अध्यक्ष. 2. जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिम जाति/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग—सदस्य. 3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—सदस्य. 4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से एक अधिकारी—सदस्य.
2	सहायक अध्यापक	अध्यापक	संबंधित विषय में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण	1. नियुक्ति प्राधिकारी नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार—अध्यक्ष.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			संबंधी उपाधि/पत्रोपाधि तथा धारित पद पर न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव.	2. जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिम जाति/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग—सदस्य. 3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—सदस्य. 4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से एक अधिकारी—सदस्य.

टिप्पण.—1. अध्यापक संवर्ग में शिक्षाकर्मियों के संविलयन के पश्चात् शिक्षाकर्मी के रूप में उनके द्वारा की गई सेवा की गणना केवल पदोन्नति/क्रमोन्नति, वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु की जाएगी.

अनुसूची—पांच

अध्यापक संवर्ग के पदों की संख्या का विवरण

1. जितनी संख्या में, शिक्षाकर्मियों का संविलयन अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर किया जाएगा, उतनी ही संख्या में पद अध्यापक संवर्ग में सृजित किए गए समझे जाएंगे.

2. जितनी संख्या में, संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर की जाएगी, उतनी ही संख्या में पद अध्यापक संवर्ग में सृजित किए गए समझे जाएंगे एवं उतनी संख्या में संविदा शाला शिक्षक संवर्ग से पद समाप्त किए गए समझे जाएंगे.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्र. 39-1692-08-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 39-1692-08-अठारह-3, दिनांक 17 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघव चन्द्रा, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th September 2008

No. 39-1692-08-XVIII-3.—In exercise of the Powers conferred by Section 433 read with sub-section (2) of Section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Section 95 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby makes the following Rules, namely ;—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Nagreeya Nikay Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Services) Rules, 2008.

(2) They shall come into force from the date of the publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी.
वि. पू. भु./04 भोपाल-2001.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 108/भोपाल/2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 मार्च 2001—फाल्गुन 29, शक 1922

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2001

क्र. एफ. 1-3-99-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 70 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2001 है.

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1

(ख) संविदा शाला शिक्षक के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची-क के [illegible] विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ग) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची-ख में दिए गए अनुसार संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति के [illegible] समिति;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) "पंचायत" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित की गई यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत;

(च) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "संविदा शाला शिक्षक" से अभिप्रेत है यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में पढ़ाने के लिये नियुक्त किया गया व्यक्ति; और

(झ) "सामान्य प्रशासन समिति" से अभिप्रेत है यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति.

3. विस्तार तथा लागू होना.--ये नियम जनपद पंचायत या जिला पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों के लिये नियुक्त किये गये "संविदा शाला शिक्षक" को लागू होंगे.

4. वर्गीकरण तथा संविदा राशि.--संविदा शिक्षकों का वर्गीकरण और उनकी संविदा राशि अनुसूची-एक में दिये गये अनुसार होगी.

5. चयन तथा भरती की पद्धति.--(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् संविदा शिक्षकों के संवर्ग की भरती, सीधी भरती के माध्यम से चयन द्वारा की जायेगी.

(2) सीधी भरती के लिये पात्रता की शर्तें.--अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी.

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध संविदा शाला शिक्षक की सीधी भरती को लागू होंगे.

(4) शासन के नियमों के अनुसार महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के लिये, जो पिछड़े वर्गों के हों, पद आरक्षित किये जायेंगे. साथ ही मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पद आरक्षित किये जायेंगे.

(5) संविदा शाला शिक्षक के पद--

(एक) क्षेत्र में अधिक संख्या में प्रचलित समाचार-पत्रों में से कम से कम किसी एक समाचार-पत्र में विज्ञापित किये जायेंगे;

(दो) स्थानीय रोजगार कार्यालय में अधिसूचित किये जाएंगे; और

(तीन) संबंधित जनपद पंचायत या जिला पंचायत, जैसी भी कि दशा हो, के सूचना फलक पर प्रदर्शित किये जायेंगे.

(6) प्राप्त आवेदनों की छानबीन करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार योग्यता सूची, पद के लिये विहित की गई अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी.

(7) चयन समिति, यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किये गये [illegible] से गठित की [illegible] सामान्यतः चयन तथा नियुक्ति का कार्य ग्रीष्मावकाश के दौरान शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के [illegible]

(8) (एक) समिति, अभ्यर्थियों का आंकलन करेगी तथा निम्नलिखित रीति से अंक देगी :—

(क) विहित अर्हता परीक्षा की वरीयता (वेटेज) देते समय अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट की गई अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के लिये 65 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे. व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले अभ्यर्थी को वरीयता (वेटेज), सैद्धान्तिक लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर दी जायेगी.

(ख) संबंधित जनपद पंचायत या जिला पंचायत के स्कूलों में अध्यापन या किसी आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अनुभव के लिये 10 प्रतिशत अंक (एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष के अनुभव के लिये) क्रमशः तीन प्रतिशत, छः प्रतिशत और दस प्रतिशत अंक दिये जायेंगे. न्यूनतम आठ मास के शैक्षणिक सत्र की गणना एक वर्ष के अनुभव के रूप में की जायेगी, और उसमें शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों, डी. पी. ई. पी., वैकल्पिक स्कूलों और औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों में अध्यापन का अनुभव भी सम्मिलित है. पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन की साक्षरता कक्षाओं को पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षकों को, जो कम से कम निरक्षर व्यक्तियों को पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन के तहत साक्षर बनायेंगे, उन्हें 3 प्रतिशत अंकों का लाभ दिया जायेगा, साक्षर उन्हें माना जायेगा, जो पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन के अधीन मापदण्ड के अनुसार मूल्यांकन में उत्तीर्ण हों. ग्रामों में शासन द्वारा शत-प्रतिशत सहायता तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्यापन के अनुभव के लिये इसी प्रकार का लाभ दिया जायेगा. ग्रामीण स्कूलों में अध्यापन के अनुभव के मूल्यांकन तथा उसके लिये प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता पर सामान्य प्रशासन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा.

(ग) डी. एड./बी. टी. आई./डी. एड. प्रमाण-पत्र के लिये 2 प्रतिशत अंक, स्काउट और गाइड/एन. सी. सी. प्रमाण-पत्र के लिये 2 प्रतिशत अंक और खेल के लिये (अंतर जिला या उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिये) 2 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे.

(घ) साक्षात्कार के लिये 10 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे.

(ङ) अंक बराबर होने की दशा में, अंतिम चयन में प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिन्हें जनपद पंचायत या जिला पंचायत के स्कूलों में अध्यापन का अनुभव है.

(दो) प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये चयन सूची, उनकी योग्यता के क्रम में उपरोक्त आंकलन के आधार पर तैयार की जाएगी और उसके अंतर्गत 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम, इनमें से जो भी अधिक हो, की प्रतीक्षा सूची होगी जो कि नौ मास की कालावधि के लिये विधिमान्य होगी. एक एकीकृत चयन सूची भी इस क्रम में तैयार की जाएगी कि अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया गया हो और अन्य नाम अवरोही क्रम में सामान्य प्रवर्ग (अनारक्षित प्रवर्ग) में रिक्तियों की संख्या तक सीमित दर्शाए गए हों. यदि सामान्य प्रवर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी है तो उसकी नियुक्ति को आरक्षित प्रवर्ग की रिक्ति के विरुद्ध नहीं माना जायेगा, इसके पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के नाम, ऐसे प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग की आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक सीमित रूप में उनकी योग्यता के क्रम में दर्शाए जायेंगे. एकीकृत चयन सूची के अंतर्गत एक प्रतीक्षा सूची भी होगी, जिसमें अभ्यर्थियों के 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम, इनमें से जो भी अधिक हो, उक्त सिद्धान्त के आधार पर होंगे.

(9) चयन सूची से नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किए गये तथा यथास्थिति, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत द्वारा रखे गये रोस्टर के अनुसार की जाएगी.

6. अनुकंपा नियुक्ति.—नियम 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायत, कलेक्टर की सिफारिशों पर, इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों या निर्देशों के अधीन अनुकंपा के आधार पर नियोजन के लिये पात्र किसी व्यक्ति को संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्त कर सकेगी.

7. सेवा में नियुक्ति.—संविदा शाला शिक्षक के पद पर सीधी भरती के माध्यम से चयनित प्रत्येक व्यक्ति, प्रारंभ में किसी विशिष्ट स्कूल के लिये तीन वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त किया जायेगा. प्रत्येक वर्ष के अंत में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा शाला शिक्षक के कार्य का आंकलन किया जाएगा. तीन वर्ष के पश्चात् संविदा शिक्षकों को उनके कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन के आधार पर एवं निर्धारित

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् पंचायत के द्वारा पुनः आगामी तीन वर्ष के लिये संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा. ऐसा व्यक्ति नवीन नियुक्ति पर उस संविदा राशि से, जो वह उसी पद पर उसकी पूर्व की पदावधि के दौरान प्राप्त कर रहा था, 15 प्रतिशत अधिक संविदा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. यदि संविदा शिक्षक का कार्य समाधानप्रद नहीं पाया जाता है तो पंचायत द्वारा उसकी सेवा समाप्त की जाएगी.

8. अनुशासन एवं नियंत्रण.—संविदा शिक्षक, यथास्थिति, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे.

9. अपील.—इन नियमों के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध कोई अपील, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जायेगी.

10. अन्य शर्तें.—

(क) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में होगा.

(ख) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार चिकित्सीय सुविधाओं तथा यात्रा भत्ते का हकदार होगा.

(ग) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति ऐसे भविष्य निधि संबंधी फायदों का हकदार होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, अवधारित किया जावे. तथापि वह किसी भी पेंशन संबंधी फायदों का हकदार नहीं होगा.

(घ) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति एक वर्ष में 15 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिवस के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा, किन्तु अन्य प्रकार के अवकाश या दीर्घावकाश का हकदार नहीं होगा.

(ङ) संविदा शाला शिक्षक तथा उनके पद स्थानान्तरणीय नहीं हैं. इन नियमों के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को यात्रा भत्ता, गृहभाड़ा या कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा.

(च) इन नियमों के अधीन सेवाओं का पर्यवसान, पदावधि के अवसान के पूर्व, किसी भी ओर से एक माह की सूचना या उसके स्थान पर एक माह की संविदा राशि देकर किसी भी समय किया जा सकेगा.

(छ) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 द्वारा शासित होगा. सेवा की कोई अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जावे.

(ज) प्रत्येक व्यक्ति से, जिसे इन नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है, परिशिष्ट-एक में दिए गए प्रपत्र में करार निष्पादित करने की अपेक्षा की जाएगी.

11. ये नियम एवं प्रक्रिया आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी लागू होंगे.

12. निर्वचन.—इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाकर जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

अनुसूची-एक

[नियम 2(ख) तथा 4 देखिए]

अनु.क्र. (1)	संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण (2)	पदों की संख्या (3)	संविदा राशि (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत) (4)	नियुक्ति प्राधिकारी (5)
1.	श्रेणी-1		रुपये 4,500	जिला पंचायत
2.	श्रेणी-2		रुपये 3,500	जनपद पंचायत
3.	श्रेणी-3		रुपये 2,500	जनपद पंचायत

टीप.—(1) संविदा शिक्षकों की विभिन्न श्रेणी के लिये पदों की संख्या का निर्धारण, यथास्थिति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा प्रमाणित किया जाएगा.

(2) सरकार केवल प्रमाणित प्रस्ताव प्राप्त होने पर, समय-समय पर, संविदा शाला शिक्षक के पद की संख्या अनुमोदित करेगी.

अनुसूची-दो

[नियम 2(ग) तथा नियम 5 देखिए]

अनु. क्र. (1)	संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण (2)	न्यूनतम आयु (3)	अधिकतम आयु (4)	शैक्षणिक अर्हता (5)	चयन समिति के सदस्य (6)
1.	श्रेणी-1	21 वर्ष	30 वर्ष	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष.	1. सभापति, जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति—अध्यक्ष. 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत—सदस्य. 3. यथास्थिति, जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास—सदस्य सचिव. 4. सामान्य प्रशासन समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी—सदस्य. 5. सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्य, जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो. यदि सामान्य प्रशासन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का एक सदस्य उपलब्ध न हो, तो ऐसे सदस्य सामान्य सभा से नामनिर्दिष्ट किए जा सकेगा—सदस्य.
2.	श्रेणी-2	21 वर्ष	30 वर्ष	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष.	1. सभापति, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति—अध्यक्ष. 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत—सदस्य. 3. यथास्थिति, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी—सदस्य सचिव. 4. सामान्य प्रशासन समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी—सदस्य. 5. सामान्य प्रशासन समिति के समस्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो. यदि सामान्य प्रशासन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का एक सदस्य उपलब्ध न हो तो ऐसे सदस्य सामान्य सभा से नामनिर्दिष्ट किए जा सकेगा—सदस्य.
3.	श्रेणी-3	18 वर्ष	30 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष.	1. सभापति, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति—अध्यक्ष. 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत—सदस्य. 3. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी—सदस्य सचिव. 4. सामान्य प्रशासन समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी—सदस्य, और. 5. सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो. यदि सामान्य प्रशासन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य उपलब्ध न हो, तो ऐसा सदस्य, सामान्य सभा से नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा—सदस्य.

टीप—(1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उच्चतर आयु-सीमा में छूट, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी.

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिये अन्य सभी छूट के अतिरिक्त उच्चतर आयु-सीमा में दस वर्ष की छूट रहेगी.

(3) जिन अभ्यर्थियों ने संबंधित जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के पर्यवेक्षण के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष तक कार्य किया है, उन्हें उच्चतर आयु-सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जा सकेगी.

(4) औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को उनकी आयु-सीमा में 8 वर्ष की छूट दी जा सकेगी.

परिशिष्ट-एक

[नियम 10 (ज) देखिए]

करार का प्रारूप

यह करार, दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को एक पक्ष के रूप में श्री ..... (जो इसमें उसके पश्चात् 'कर्मचारी' कहलायेगा) तथा दूसरे पक्ष के रूप में ..... जिला/जनपद पंचायत के लिए और उसकी ओर से जिला/जनपद पंचायत ..... के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के बीच निष्पादित किया गया.

अतः जिला/जनपद पंचायत निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों पर दिनांक ..... से कर्मचारी को ..... के रूप में काम पर लेने के लिए सहमत है.

अतएव पक्षकारों के बीच निम्नानुसार करार किया जाता है.

(1) जिला/जनपद पंचायत कर्मचारी को नियोजित करेगी तथा कर्मचारी तारीख ..... से ..... के रूप में जिला/जनपद पंचायत की सेवा करेगा;

(2) कर्मचारी तारीख ..... से ..... वर्षों की कालावधि के लिए जिला/जनपद पंचायत में इसमें इसके पश्चात् उपबंधित किए गए अनुसार सेवा के पूर्व पर्यवसान के अध्यधीन रहते हुए सेवा करेगा;

(3) कर्मचारी अपना संपूर्ण समय सेवा के कर्तव्यों के प्रति समर्पित करेगा तथा अपने स्वयं को किसी व्यापार, कारबार या जीविका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं लगाएगा और जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से पहले अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना (दुर्घटना के सिवाय या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का बीमारी का प्रमाण-पत्र दिये जाने के सिवाय) स्वयं को अनुपस्थित नहीं रखेगा;

(4) कर्मचारी को उसकी पदस्थापना के स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा और उसे अपनी पदस्थापना के स्थान पर अपना मुख्यालय रखना होगा;

(5) इस करार का पर्यवसान, उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को उस आशय की लिखित में कम से कम एक केलेण्डर मास की सूचना देकर किया जा सकेगा और जिला/जनपद पंचायत द्वारा या उसकी ओर से दी गई ऐसी किसी सूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पर्याप्त सूचना है, यदि वह कर्मचारी को संबोधित तथा उसके निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी गई है :

परन्तु कर्मचारी की सेवायें बिना किसी सूचना के भी समाप्त की जा सकेगी और कर्मचारी को एक मास के वेतन की दर से प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा ;

परन्तु यदि करार का पर्यवसान किसी कर्मचारी द्वारा एक मास की अपेक्षित सूचना दिए बिना संविदा कालावधि के अवसान के पूर्व किया जाता है तो वह एक मास के वेतन की दर से प्रतिकर का भुगतान जिला/जनपद पंचायत को करेगा;

(6) किसी कर्मचारी की सेवाएं किसी भी समय बिना किसी सूचना के सेवाओं से समाप्त की जा सकेगी यदि कर्मचारी व्यक्तिगत अवचार का दोषी पाया जाए या इस करार के निबंधनों या अपने कर्तव्यों या समय-समय पर उसे सौंपे गये किन्हीं कर्तव्यों का जानबूझकर उल्लंघन या उसकी उपेक्षा का दोषी पाया जाए;

(7) कर्मचारी को अपने नियोजन की अवधि के दौरान अपनी सेवाओं के पारिश्रमिक के रूप में रुपये ..... का भुगतान किया जाएगा;

(8) कर्मचारी को किसी भी पेंशन की पात्रता नहीं होगी.

(9) इस करार के खण्ड (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जिला/जनपद पंचायत के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस करार के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय सम्यक् रूप से गठित सलाहकार चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट से उसका इस बात से समाधान हो जाने पर कि उसकी सेवाओं को इस विलेख के अधीन अवसान कर दे कि कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के योग्य नहीं है और उसके खराब स्वास्थ्य की वजह से विचारार्थ कालावधि के लिए अयोग्य बने रहने की संभावना है और तदुपरि उसकी सेवाएं उसे पन्द्रह दिन की सूचना देकर समाप्त कर दी जाएगी इस प्रकार सेवा समाप्ति की दशा में जिला/जनपद पंचायत कर्मचारी को संविदा की अवसित कालावधि के लिये किसी भी प्रतिकर का भुगतान करने के दायित्वाधीन नहीं होगी;

(10) कर्तव्य के दौरान यात्रा करने के लिए कर्मचारी को ऐसी दर से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी जैसा कि जिला/जनपद पंचायत द्वारा समय-समय पर घोषित किया जाए;

(11) कर्मचारी को अपने नियोजन के दौरान इस निमित्त विहित किए गए अवकाश नियमों के अनुसार अवकाश अनुज्ञात किया जाएगा.

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने इस विलेख को ऊपर लिखी तारीख . . . . . माह . . . . . वर्ष 2001 को लिखकर करके निम्नलिखित की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए . . . . . जिला पंचायत/जनपद पंचायत की मुहर लगाई गई.

उपस्थिति में—

1. . . . . (1) हस्ताक्षर . . . . . .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला/जनपद पंचायत,

2. . . . . (2) कर्मचारी के हस्ताक्षर (नाम)

जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री . . . . . के मुद्रा सहित हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एस. अहलावत, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2001

क्र. एफ. 1-3-99-बाईस-पं-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एस. अहलावत, अपर सचिव.

Bhopal, the 20th March 2001

No. F-1-3-99-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 70 read with sub-section (1) of Section 95 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby makes the following Rules, the same having been previously publishes as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely :—

RULES

1. **Short title and Commencement.**—(1) These Rules may be called the Madhya Pradesh Panchayat Sanvida Shala Shikshak (Appointment and conditions of services) Rules, 2001.

(33) (78)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल

क्रमांक एफ–1–3/2013/22/पं–2 भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषयः– अध्यापक संवर्ग को संशोधित वेतनमान दिये जाने के संबंध में ।

——0——

ग्रामीण स्थानीय निकायों (जिला पंचायत/जनपद पंचायत) के अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग को वर्तमान में दिए जा रहे वेतनमान के स्थान पर निम्नानुसार वेतन बैंड एवं संवर्ग वेतन दिनांक 01.04.2013 से दिया जाता है:–

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग का पदनाम	वेतन–बैंड	संवर्ग वेतन
1	वरिष्ठ अध्यापक	₹ 4500-25000	₹ 1900 –
2	अध्यापक	₹ 4500-25000	₹ 1650 –
3	सहायक अध्यापक	₹ 4500-25000	₹ 1250 –

2/ दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में अध्यापक संवर्ग को नवीन वेतन बैंड में वेतन नियमन निम्नानुसार ज्ञात किया जाएगा:–

2.1 वर्तमान में प्राप्त हो रहे मूल वेतन में 1.62 गुणा वृद्धि कर नवीन मूल वेतन प्राप्त होगा, जिसे अगले 10 रुपये पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।

2.2 नवीन वेतन बैंड में वेतन की गणना किए जाने पर वेतन एवं संवर्ग वेतन का 72 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाएगा।

3/ वरिष्ठ अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी:--

स. क्र.	वर्तमान मूल वेतन	मूल वेतन का 1.62 गुणा	नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10रुपये के पूर्णांक में)	संवर्ग वेतन	मंहगाई भत्ता	नवीन वेतन बैंड में मंहगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	5000	8100	8100	1900	7200	17200
2	5175	8384	8390	1900	7409	17699
3	5350	8667	8670	1900	7610	18180
4	5525	8951	8960	1900	7819	18679
5	5700	9234	9240	1900	8021	19161
6	5875	9518	9520	1900	8222	19642
7	6050	9801	9810	1900	8431	20141
8	6225	10085	10090	1900	8633	20623
9	6400	10368	10370	1900	8834	21104
10	6575	10652	10660	1900	9043	21603

4/ अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी:-

स.क्र.	वर्तमान मूल वेतन	मूल वेतन का 1.62 गुणा	नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10 रुपये के पूर्णांक में)	संवर्ग वेतन	मंहगाई भत्ता	नवीन वेतन बैंड में मंहगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	4000	6480	6480	1650	5854	13984
2	4125	6683	6690	1650	6005	14345
3	4250	6885	6890	1650	6149	14689
4	4375	7088	7090	1650	6293	15033
5	4500	7290	7290	1650	6437	15377
6	4625	7493	7500	1650	6588	15738
7	4750	7695	7700	1650	6732	16082
8	4875	7898	7900	1650	6876	16426
9	5000	8100	8100	1650	7020	16770
10	5125	8303	8310	1650	7171	17131

3/5

5/ सहायक अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी :-

स. क्र.	वर्तमान मूल वेतन	मूल वेतन का 1.62 गुणा	नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10रुपये के पूर्णांक में)	संवर्ग वेतन	मंहगाई भत्ता	नवीन वेतन बैंड में मंहगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	3000	4860	4860	1250	4399	10509
2	3100	5022	5030	1250	4522	10802
3	3200	5184	5190	1250	4637	11077
4	3300	5346	5350	1250	4752	11352
5	3400	5508	5510	1250	4867	11627
6	3500	5670	5670	1250	4982	11902
7	3600	5832	5840	1250	5105	12195
8	3700	5994	6000	1250	5220	12470
9	3800	6156	6160	1250	5335	12745
10	3900	6318	6320	1250	5450	13020

6/ वेतन वृद्धि की गणना एवं तिथि:- नवीन वेतन बैंड में वेतन वृद्धि की गणना हेतु वेतन बैंड में वेतन एवं संवर्ग वेतन का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर वेतन बैंड में वेतन निर्धारित किया जाएगा। दिनांक 01.04.2013 को वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप सभी अध्यापक संवर्ग के अध्यापकों की आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.10.2013 होगी।

(37) (82)

20

7/ क्रमोन्नति पर वेतन निर्धारण:- क्रमोन्नति प्राप्त होने की स्थिति में वेतन बैंड में वेतन (संवर्ग वेतन को छोड़कर) का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर मूल वेतन एवं बढ़ा हुआ संवर्ग वेतन दिया जावेगा।

8/ पदोन्नति पर वेतन निर्धारण:- पदोन्नति की स्थिति में वेतन बैंड में वेतन तथा वर्तमान में प्राप्त संवर्ग वेतन का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर वेतन बैंड में वेतन निर्धारित किया जाएगा एवं बढ़ा हुआ संवर्ग वेतन दिया जावेगा।

यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ली गई वित्त विभाग की सहमति टीप क्रमांक यू.ओ.क. 349/362/13/ नियम/चार दिनांक 18.2.2013 के अनुशरण में जारी किया गया है ।

(ब्रजेश कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठांक एफ-1-3/2013/22/पं-2 भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2013

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र.शासन
3. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आदिवासी विकास विभाग, ।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग ।
7. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल
8. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश ।
9. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म.प्र.।
10. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
11. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र.।
12. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(38) (85)

Annexure P-7

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

दिनांक 25/02/2016

आदेश

क्रमांक– एफ–1–31/2013/22/पं–2 समसंख्यक आदेश दिनांक 04.09.2013 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अध्यापक संवर्ग को दिनांक 01.01.2016 से निम्नानुसार छठवां वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :–

अध्यापक संवर्ग	वेतन बैण्ड रुपये	ग्रेड–पे रुपये	महगाई भत्ता।
वरिष्ठ अध्यापक	रू. 9300–34800	रू.3600	दिनांक 01.1.2016 से शासकीय कर्मचारी को देय महगाई भत्ते के तुल्य एवं समय–समय पर की जाने वाली वृद्धि सहित
अध्यापक	रू. 9300–34800	रू.3200	
सहायक अध्यापक	रू. 5200–20200	रू.2400	

2 छठवां वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से देय है। वेतनमान का नगद भुगतान 01.04.2016 (मई, 2016 में देय) से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2016 तक की बकाया राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया जायेगा।

3. छठवे वेतनमान अंतर्गत वेतन निर्धारण संबंधी विस्तृत निर्देश वित्त विभाग की सहमति से पृथक से जारी किये जायेंगे।

4. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 244/16/वि/दस दिनांक 25/2/16 के अनुसार पृष्ठांकित किया गया है।

(वित्त)
244/16/वि/दस
25/2/16 द्वारा पृष्ठांकित

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ब्रजेश कुमार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(39) (86)

पृष्ठांकन क्रमांक एफ–1–31/2013/22/पं–2 दिनांक 15.02.2016

प्रतिलिपि–

1. माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्टॉफ आफिसर।
5. निज सहायक/निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/ वित्त/ नगरीय प्रशासन एवं विकास/ आदिम जाति कल्याण/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. महालेखाकार मध्यप्रदेश, भोपाल/ग्वालियर।
7. आयुक्त, पंचायतराज/लोक शिक्षण/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आदिम जाति कल्याण/ अनुसूचित जाति कल्याण/आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ
9. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला एवं जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
15. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(40) (94)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

52

आदेश

क्रमांक–एफ–1–31/2013/22/पं-2 भोपाल, दिनांक 7.07.2017

राज्य शासन विभाग के आदेश दिनांक 04.09.2013 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा नियुक्त सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक संवर्गों को राज्य शासन के अधीन नियुक्त शिक्षक संवर्गों के समान छठवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान (आगे इसे छठवां वेतनमान कहा जायेगा) दिनांक 01.09.2017 से स्वीकृत करने तथा उक्त संवर्ग को विद्यमान वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतन एवं छठवें वेतनमान में प्राप्त होने वाले वेतन के अंतर की राशि को अंतरिम राहत के रूप मे चार वार्षिक किस्तों में प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। इस अंतरिम राहत के निर्धारण के लिये अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना का सिद्धांत रखा गया था। राज्य शासन के आदेश क्रमांक–एफ–1–31/2013/22/पं–2 दिनांक 25.02.2016 द्वारा अध्यापक संवर्गों को छठवां वेतनमान दिनांक 01.09.2017 के स्थान पर दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत किया गया।

2. उपर्युक्त आदेश के परिपालन में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2016 एवं आदेश दिनांक 15.10.2016 द्वारा सहायक अध्यापक, अध्यापक तथा वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में कार्यरत अध्यापकों के विद्यमान वेतनमान से छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण की कतिपय विसंगतियों की ओर अध्यापक संवर्ग द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया, परिणामस्वरूप आदेशों का क्रियान्वयन स्थगित रखा गया। समग्र विचारोपरांत उपर्युक्त आदेश दिनांक 31.05.2016 एवं आदेश दिनांक 15.10.2016 एतद् द्वारा निरस्त किये जाते है तथा अध्यापक संवर्ग को दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु निम्नानुसार सिद्धांत एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(अ) छठवे वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिये सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पर पूर्ण की गई सेवा अवधि के आधार पर परिशिष्ट–1, परिशिष्ट-2, तथा परिशिष्ट–3 में उल्लेखित अनुसार छठवें वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में उस सेवा अवधि (पूर्ण वर्ष) के सम्मुख दर्शाये गये संबंधित प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ब) छठवे वेतनमान में वेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग के तीन प्रतिशत के बराबर होगी, जो कि रूपये 10 के अगले गुणांक में पूर्णांकित होगी।

(स) तत्स्थानी वेतनमान में वेतन वृद्धि की तिथि सामान्य रूप से 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को छठवें वेतनमान के ढांचे में 6 माह या अधिक अवधि पूरा करने वाले वेतन वृद्धि के लिये पात्र होंगे।

3. राज्य शासन के अधीन नियुक्त शिक्षक संवर्गों के लिये पदोन्नति तथा क्रमोन्नति वेतनमान के लिये समय–समय पर जारी सेवा शर्तें, निर्देश, मापदंड अध्यापक संवर्गों पर भी तदनुसार प्रभावशील होंगे। क्रमोन्नत वेतनमान में म.प्र.मूलभूत नियम तथा राज्य शासन वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत वेतन निर्धारित होगा।

4. इस आदेश के अंतर्गत जारी निर्देशों में वेतन निर्धारण में यदि किसी प्रकरण में कोई दुविधा अथवा भ्रांति उद्भुद होती है तो इसका निराकरण इस विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से किया जाये।

5. परिपत्र के पैरा 2 (अ) से पृथक वेतन निर्धारण कर भुगतान किये गये प्रकरणों का पुनः परीक्षण कर वेतन निर्धारण को यथा संशोधित किया जावे । अनियमित अथवा अधिक भुगतान की स्थिति में आधिक्य राशि का समायोजन/वसूली का दायित्व संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा। वेतन निर्धारण की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करने का उत्तरदायित्व उस कार्यालय प्रमुख का होगा जिस कार्यालय में सेवापुस्तिका संधारित है।

6. वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किये जाने वाले स्वत्वों के भुगतान से पूर्व संबंधित से परिशिष्ट– 'चार' पर उल्लेखित प्रपत्र में वचन पत्र प्राप्त किया जाये।

7. अध्यापक संवर्गों को छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिये विकल्प निर्धारित प्रारूप में इस आदेश के जारी होने के 3 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा । विकल्प प्रारूप परिशिष्ठ –'पांच' पर संलग्न है ।

8. अध्यापक संवर्गों को छठवां वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से देय है। जुलाई, 2017 का वेतन जो अगस्त, 2017 में भुगतान होगा, से नगद तथा दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2017 तक की बढी हुई राशि का भुगतान तीन किस्तों में क्रमशः वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में किया जायेगा। एरियर्स की राशि तथा इसके भुगतान की प्रवृष्टि सेवा–पुस्तिका में की जाए।

9. इस आदेश के अंतर्गत जारी वेतनमान में किये गये वेतन निर्धारण का अनुमोदन जिला पंचायतों में पदस्थ वरिष्ठ लेखा अधिकारी अथवा लेखा अधिकारी से कराया जावे।

10. यह आदेश वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1118/1382/2017/नियम/चार दिनांक 06.07.2017 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.आर.चौधरी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक--एफ--1--31/2013/22/पं-2 दिनांक 7 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि-

1. माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्टॉफ आफिसर।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/ वित्त/ नगरीय प्रशासन एवं विकास/ आदिम जाति कल्याण/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, भोपाल/ग्वालियर।
7. आयुक्त, पंचायत/लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आदिम जाति कल्याण/ अनुसूचित जाति कल्याण/आयुक्त कोष एवं लेखा/जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल।
8. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला एवं जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
15. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

07.01.17

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट – 1

दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत 6वें वेतनमान दिए जाने पर वेतन निर्धारण तालिका

सहायक अध्यापक

सेवावधि	विद्यमान वेतनमान (4500–25000+1250)			6वां वेतनमान (5200–20200+2400)		
	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग
प्रारंभ	4860	1250	6110	7440	2400	9840
1 वर्ष	5030	1250	6280	7630	2400	10030
2 वर्ष	5190	1250	6440	7820	2400	10220
3 वर्ष	5350	1250	6600	8000	2400	10400
4 वर्ष	5510	1250	6760	8190	2400	10590
5 वर्ष	5670	1250	6920	8370	2400	10770
6 वर्ष	5840	1250	7090	8560	2400	10960
7 वर्ष	6000	1250	7250	8750	2400	11150
8 वर्ष	6160	1250	7410	8930	2400	11330
9 वर्ष	6320	1250	7570	9120	2400	11520
10 वर्ष	6480	1250	7730	9300	2400	11700
11 वर्ष	6650	1250	7900	9490	2400	11890
12 वर्ष	6810	1250	8060	9680	2400	12080
13 वर्ष	6970	1250	8220	9860	2400	12260
14 वर्ष	7130	1250	8380	10050	2400	12450

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ठ – 2

दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत 6वें वेतनमान दिए जाने पर वेतन निर्धारण तालिका

अध्यापक

सेवावधि	विद्यमान वेतनमान (4500–25000+1650)			6वां वेतनमान (9300–34800+3200)		
	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग
प्रारंभ	6480	1650	8130	9300	3200	12500
1 वर्ष	6690	1650	8340	9580	3200	12780
2 वर्ष	6890	1650	8540	9860	3200	13060
3 वर्ष	7090	1650	8740	10140	3200	13340
4 वर्ष	7290	1650	8940	10420	3200	13620
5 वर्ष	7500	1650	9150	10700	3200	13900
6 वर्ष	7700	1650	9350	10980	3200	14180
7 वर्ष	7900	1650	9550	11260	3200	14460
8 वर्ष	8100	1650	9750	11540	3200	14740
9 वर्ष	8310	1650	9960	11820	3200	15020
10 वर्ष	8510	1650	10160	12090	3200	15290
11 वर्ष	8710	1650	10360	12370	3200	15570
12 वर्ष	8910	1650	10560	12650	3200	15850
13 वर्ष	9120	1650	10770	12930	3200	16130
14 वर्ष	9320	1650	10970	13210	3200	16410

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ठ – 3

दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत 6वें वेतनमान दिए जाने पर वेतन निर्धारण तालिका

वरिष्ठ अध्यापक

सेवावधि	विद्यमान वेतनमान (4500–25000+1900)			6वां वेतनमान (9300–34800+3600)		
	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग
प्रारंभ	8100	1900	10000	10230	3600	13830
1 वर्ष	8390	1900	10290	10560	3600	14160
2 वर्ष	8670	1900	10570	10890	3600	14490
3 वर्ष	8960	1900	10860	11210	3600	14810
4 वर्ष	9240	1900	11140	11540	3600	15140
5 वर्ष	9520	1900	11420	11860	3600	15460
6 वर्ष	9810	1900	11710	12190	3600	15790
7 वर्ष	10090	1900	11990	12510	3600	16110
8 वर्ष	10370	1900	12270	12840	3600	16440
9 वर्ष	10660	1900	12560	13160	3600	16760
10 वर्ष	10940	1900	12840	13490	3600	17090
11 वर्ष	11220	1900	13120	13820	3600	17420
12 वर्ष	11510	1900	13410	14140	3600	17740
13 वर्ष	11790	1900	13690	14470	3600	18070
14 वर्ष	12070	1900	13970	14790	3600	18390
15 वर्ष	12360	1900	14260	15120	3600	18720
16 वर्ष	12640	1900	14540	15440	3600	19040

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

46 100

69

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 23/8/2017

क्रमांक-एफ-1-31/2013/22/पं.-2 : जिला/जनपद पंचायत अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग को विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2017 द्वारा छठवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान (आगे इसे छठवां वेतनमान कहा जाये) दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत किया गया है। आदेश की कंडिका- 2 (अ) में 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस अनुक्रम में स्पष्ट किया जाता है कि यही प्रक्रिया विद्यमान वेतनमान में क्रमोन्नत/पदोन्नत वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे अध्यापकों के वेतन निर्धारण में भी प्रभावी रहेगी। विद्यमान वेतनमान में रू0 1650 संवर्ग वेतन प्राप्त सहायक अध्यापक, रू0 4900 संवर्ग वेतन प्राप्त अध्यापक के क्रमोन्नत एवं छठवें वेतनमान की तालिकायें संदर्भित आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट- दो एवं तीन में दर्शित हैं। विद्यमान वेतनमान में रू0 2150 संवर्ग वेतन प्राप्त वरिष्ठ अध्यापक को 6वें वेतनमान में क्रमोन्नति के प्रथम सोपान की पात्रता होगी। तदनुसार वेतनमान/पदोन्नत वेतनमान 9300-34800 + 4200 ग्रे. पे. के तथा वरिष्ठ अध्यापक के वेतन क्रमोन्नति/पदोन्नति वेतनमान में सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के वेतन निर्धारण के लिए वेतन तालिका क्रमांक परिशिष्ट- क में पृथक संलग्न है।

2. विद्यमान वेतनमान में क्रमोन्नत/पदोन्नत वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों का छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण संदर्भित आदेश दिनांक 07.07.2017 की कंडिका 2 (अ) के अनुक्रम में संलग्न परिशिष्टों में विद्यमान वेतनमान अंतर्गत अंकित सेवा अवधि के सम्मुख छठवें वेतनमान अंतर्गत दर्शाये गये प्रक्रम पर किया जावेगा।

3. संदर्भित आदेश दिनांक 07.07.2017 की कंडिका-3 में अध्यापक संवर्ग के लिये पदोन्नति तथा क्रमोन्नति के संबंध में जारी किये गये निर्देश दिनांक 01.01.2016 से पश्चात की गई पदोन्नतियों/क्रमोन्नतियों पर प्रभावशील होंगे।

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा यू.ओ.नं. क्रमांक-1364/1744/17/वित्त/नियम/चार दिनांक 11.08.2017 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. मसूद अख्तर)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

//Desktop/Scan/RSatankar//

पृष्ठांकन क्रमांक–एफ–1–31/2013/22/पं.–2 दिनांक 22/12/2017

प्रतिलिपि–

1. माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्टॉफ आफिसर।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/ वित्त/ नगरीय प्रशासन विभाग/आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, भोपाल/ग्वालियर।
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
9. आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
10. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश।
11. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
12. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ
13. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
14. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
17. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
18. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
19. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

71

परिशिष्ट – क

अध्यापक संवर्ग को स्वीकृत 6वें वेतनमान में क्रमोन्नत/ पदोन्नत अध्यापकों के वेतन निर्धारण हेतु तालिका

सहायक अध्यापक

क्रमोन्नत/पदोन्नत वेतनमान (4500–25000+1650) में सेवा अवधि (पूर्ण वर्षों में)	छठवां वेतन (9300–34800+3200)		
	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग
प्रारंभ	9300	3200	12500
1 वर्ष	9580	3200	12780
2 वर्ष	9860	3200	13060
3 वर्ष	10140	3200	13340
4 वर्ष	10420	3200	13620
5 वर्ष	10700	3200	13900
6 वर्ष	10980	3200	14180
7 वर्ष	11260	3200	14460
8 वर्ष	11540	3200	14740
9 वर्ष	11820	3200	15020

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

//Desktop/Scan/RSatankar//

परिशिष्ट – ख

अध्यापक संवर्ग को स्वीकृत 6वें वेतनमान में क्रमोन्नत / पदोन्नत अध्यापकों के वेतन निर्धारण हेतु तालिका

अध्यापक

क्रमोन्नत/पदोन्नत वेतनमान (4500–25000+1900) में सेवा अवधि (पूर्ण वर्षों में)	छठवां वेतनमान (9300–34800+3600)		
	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग
प्रारंभ	10230	3600	13830
1 वर्ष	10560	3600	14160
2 वर्ष	10890	3600	14490
3 वर्ष	11210	3600	14810
4 वर्ष	11540	3600	15140
5 वर्ष	11860	3600	15460
6 वर्ष	12190	3600	15790
7 वर्ष	12510	3600	16110
8 वर्ष	12840	3600	16440
9 वर्ष	13160	3600	16760

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
ग्रा.वि. विकास एवं पंचायत विभाग

अध्यापक संवर्ग को स्वीकृत 6वें वेतनमान में क्रमोन्नत/पदोन्नत अध्यापकों के वेतन निर्धारण हेतु तालिकाएं

वरिष्ठ अध्यापक

73

क्रमोन्नत/पदोन्नत वेतनमान (4500-25000+2150) में सेवा अवधि (पूर्ण वर्षों में)	छठवां क्रमोन्नत वेतनमान (9300-34800+4200)		
	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	सवर्ग वेतन	योग
1	2	3	2
प्रारंभ	12090.00	4200.00	16290.00
1 वर्ष	12470.00	4200.00	16670.00
2 वर्ष	12840.00	4200.00	17040.00
3 वर्ष	13210.00	4200.00	17410.00
4 वर्ष	13580.00	4200.00	17780.00
5 वर्ष	13950.00	4200.00	18150.00
6 वर्ष	14330.00	4200.00	18530.00
7 वर्ष	14700.00	4200.00	18900.00
8 वर्ष	15070.00	4200.00	19270.00
9 वर्ष	15440.00	4200.00	19640.00

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

(51) (105)

74

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 1–31/2013/22/पं.–2

भोपाल, दिनॉक 29.12.2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र. ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
7. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय :– अध्यापक संवर्ग को स्वीकृत 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण।

—00—

अध्यापक संवर्ग में पदोन्नति/क्रमोन्नति वेतनमान में स्वीकृत 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के संबंध में विभाग के आदेश क्रमांक एफ–1–31/2013/22/पं–2 दिनांक 22.08.2017 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश की कंडिका–2 में उल्लेखित है कि वेतन निर्धारण विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2017 की "कंडिका– 2(अ) के अनुक्रम में संलग्न परिशिष्टों में विद्यमान वेतनमान अंतर्गत अंकित सेवा अवधि के सम्मुख छठवें वेतनमान अंतर्गत दर्शाये गये प्रक्रम पर किया जायेगा।" कतिपय कार्यालयों द्वारा इस बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा गया था कि अध्यापक संवर्ग में पदोन्नति/क्रमोन्नति प्राप्त अध्यापकों के प्रकरणों में वेतन निर्धारण के लिए सेवा अवधि की गणना किस दिनांक से की जानी है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि क्रमोन्नति/पदोन्नति के प्रकरणों में परिपत्र दिनांक 07.07.2017 की कंडिका– 2(अ) अनुसार वेतन निर्धारण के लिए सेवा अवधि की गणना अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से की जावेगी तथा तदनुसार पूर्ण वर्षों के आधार पर सम्मुख प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

2. अध्यापक संवर्ग के 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रक्रिया के संबंध में विभाग के आदेश दिनांक 07.07.2017 एवं 22.08.2017 के अनुक्रम में विभिन्न श्रेणी के वेतन निर्धारण के उदाहरण संलग्न परिशिष्ट–'1 से परिशिष्ट–'4' पर अंकित हैं।

...2...

Gulshan Chouhan-A

3. उपरोक्त स्पष्टीकरण तथा मार्गदर्शी उदाहरण वित्त विभाग द्वारा यू.ओ.नोट क्रमांक 2071/1382/17/वित्त/नियम/चार दिनांक 5.12.2017 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी किए गए हैं।

संलग्नः– परिशिष्ट–1 से 4

(एस.आर.चौधरी)
उप सचिव
म.प्र.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठां.कमांक एफ 1–31/2013/22/पं.–2

भोपाल, दिनॉक 29.12.2017.

1. माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्टॉफ आफिसर।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/ वित्त/ नगरीय प्रशासन विभाग/आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, भोपाल/ग्वालियर।
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश ।
9. आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
10. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश।
11. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
12. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ
13. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

29-XII-17
उप सचिव
म.प्र.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Gulshan Chouhan-A

परिशिष्ट–एक

सहायक अध्यापक (वेतनमान– 5200–20200+2400)

1.	शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	दिनांक 01.01.2016 को कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
4.	आदेश दि.07.07.2017 की कंडिका–2 (अ) के अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
5.	6वें वेतनमान में वेतनमान	5200–20200+2400
6.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 07.07.17 के परिशिष्ट – 1 की तालिका के कॉलम–1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख)	8930+2400=11330
7	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

सहायक अध्यापक (क्रमोन्नत/पदोन्नत वेतनमान– 9300–34800+3200)

1.	शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमोन्नति अथवा पदोन्नति दिनांक	01.10.2010
4.	दिनांक 01.01.2016 को अध्यापक संवर्ग में की गई कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
5.	आदेश दि.22.08.2017 की कंडिका–2 सहपठित आदेश दि.07.07.17 की कंडिका– 2 (अ) अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
6.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300–34800+3200
7.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 22.08.17 के परिशिष्ट– 'क' की तालिका के कॉलम–1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख)	11540+3200=14740
8.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Gulshan Chouhan-A

परिशिष्ट–दो

अध्यापक (वेतनमान– 9300–34800+3200)

1.	शिक्षाकर्मी वर्ग–2 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	दिनांक 01.01.2016 को कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
4.	आदेश दि.07.07.2017 की कंडिका–2 (अ) के अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
5.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300–34800+3200
6.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 07.07.17 के परिशिष्ट – 2 की तालिका के कॉलम–1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख)	11540+3200=14740
7.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

अध्यापक (क्रमोन्नत/पदोन्नत वेतनमान– 9300–34800+3600)

1.	शिक्षाकर्मी वर्ग–2 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमोन्नति अथवा पदोन्नति दिनांक	01.10.2010
4.	दिनांक 01.01.2016 को अध्यापक संवर्ग में की गई कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
5.	आदेश दि.22.08.2017 की कंडिका–2 सहपठित आदेश दि.07.07.17 की कंडिका– 2 (अ) अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
6.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300–34800+3600
7.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 22.08.17 के परिशिष्ट– 'ख' की तालिका के कॉलम–1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख)	12840+3600=16440
8.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट–तीन

70

वरिष्ठ अध्यापक (वेतनमान– 9300–34800+3600)

1.	शिक्षाकर्मी वर्ग–1 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	दिनांक 01.01.2016 को कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
4.	आदेश दि.07.07.2017 की कंडिका–2 (अ) के अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
5.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300–34800+3600
6.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 07.07.17 के परिशिष्ट – 3 की तालिका के कॉलम–1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख	12840+3600=16440
7	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

वरिष्ठ अध्यापक (क्रमोन्नत वेतनमान– 9300–34800+4200)

1.	शिक्षाकर्मी वर्ग–1 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमोन्नति का दिनांक	01.10.2010
4.	दिनांक 01.01.2016 को अध्यापक संवर्ग में की गई कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
5.	आदेश दि.22.08.2017 की कंडिका–2 सहपठित आदेश दि.07.07.17 की कंडिका–2 (अ) अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
6.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300–34800+4200
7.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 22.08.17 के परिशिष्ट– 'ग' की तालिका के कॉलम–1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख	15070+4200=19270
8.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट–चार 79

संविदा शाला शिक्षक वर्ग–3 का संविलियन सहायक अध्यापक के पद पर होने पर वेतन निर्धारण

1.	संविदा शाला शिक्षक वर्ग–3 के पद पर नियुक्ति	दिनांक 01.10.2011
2.	सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन	दिनांक 01.10.2014
3	सहायक अध्यापक पद का वेतनमान	5200–20200+2400
4	नियुक्ति दिनांक 01.10.2014 से 31.12.2015 तक कुल सेवा अवधि	एक वर्ष दो माह अर्थात् सेवावधि–01 पूर्ण वर्ष
5	दिनांक 01.01.2016 को वेतन प्रक्रम	7630+2400=10030
6	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक	01.07.2016

संविदा शाला शिक्षक वर्ग–2 का संविलियन अध्यापक के पद पर होने पर वेतन निर्धारण

1.	संविदा शाला शिक्षक वर्ग–2 के पद पर नियुक्ति	दिनांक 01.04.2012
2.	अध्यापक के पद पर संविलियन	दिनांक 01.04.2015
3	अध्यापक पद का वेतनमान	9300–34800+3200
4	दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में वेतन	9300+3200=12500
5	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक	01.07.2016

संविदा शाला शिक्षक वर्ग–1 का संविलियन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर होने पर वेतन निर्धारण

1	संविदा शाला शिक्षक वर्ग–1 के पद पर नियुक्ति	दिनांक 01.07.2013
2	वरिष्ठ अध्यापक के पद पर संविलियन	दिनांक 01.07.2016
3.	वरिष्ठ अध्यापक पद का वेतनमान	9300–34800+3600
4	नियुक्ति दिनांक 01.07.2016 / 31.07.2016 की स्थिति में वेतन	10230+3600=13830
5	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक	01.07.2017

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 1–55/09/20–1
प्रति

भोपाल,दिनांक 13-10-2009

1. समस्त कलक्टर
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत / सहायक पंचायत
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश

विषय–ग्रीन कार्डधारक शिक्षाकर्मियों / अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने बाबत।

–00–

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1–10/2005/20–1, दिनांक 16.6.06 द्वारा ग्रीनकार्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए है। प्रदेश में दिनांक 01.04.07 से शिक्षाकर्मियों के संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:–

1. शिक्षाकर्मी/अध्यापक संवर्ग के रूप में कार्यरत रहते हुये परिवार नियोजन के लिये आपरेशन करवाने वाले शिक्षाकर्मियों/अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी।
2. दिनांक 16.06.2006 के पूर्व परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को दिनांक 16.06.2006 से एवं इस दिनांक के उपरांत परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को परिवार नियोजन कराने के दिनांक से अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त होगा।

शेष निर्देश विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1–10/2005/20–1, दिनांक 16.06.06 में उल्लेखित अनुसार यथावत लागू रहेंगे। वित्त विभाग द्वारा इस विभाग की नस्ती पर उनके यू0ओ0 क्रमांक 1863/प.क.प्र./चार, दिनांक 12.10.2009 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

(एस0एन0शर्मा)
उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक एफ–1–55/09/20–1
भोपाल,दिनांक 13-10-200

प्रतिलिपि:–

1. निज सहायक, मा. मंत्रीजी, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त/पंचायत एवं ग्रामीण विकास /नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

13/10/09
उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल– 462004

क्रमांक एफ 1–10/2005/20–1 भोपाल,दिनांक 16/06/2006

प्रति

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
2. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
3. समस्त, आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.।
4. समस्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, म.प्र.।
5. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।

विषय–ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

—0—

राज्य शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. सी–3/9/2001/1/3, दिनांक 07.06.2001 के अनुसार शिक्षाकर्मियों का भी स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियां निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की सहमति प्रदान की जाती है :–

1. एक जीवित बच्चे के बाद स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जायेगी।
2. दो जीवित बच्चों के बाद स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जायेगी।
3. जो शिक्षाकर्मी आदेश जारी होने के पश्चात् ग्रीन कार्ड प्राप्त करेंगे उन्हें ही अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा।

2. ये निर्देश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे।

2. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्र. 1126/06/नि./चार, दिनांक 07.06.06 द्वारा महालेखाकार को पृष्ठांकित किया गया है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुष्पलता सिंह)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक–3350

संक्षेपिका

क्र.	संबंधित प्रश्न	उत्तर
1	शिक्षा गारंटी योजना कब प्रारम्भ हुई।	फरवरी 1997 से
2	ई.जी.एस. खोलने का मापदण्ड	प्राथमिक शिक्षा की सुविधा एक किमी. की दायरे में न होने पर एवं 5 से 14 वर्ष के सामान्य क्षेत्र में 40 बच्चे तथा आदिवासी क्षेत्रों में कम से कम 25 बच्चे होने पर ग्राम सभा के मांग पर।
3	गुरूजी के चयन का मापदण्ड	• गुरूजी की पहचान वहीं समुदाय करता है। जिसने शाला खोलने की मांग की है। • गुरूजी स्थानीय व्यक्ति होगा। अर्थात् उसी बसाहट का जहां शिक्षा गारंटी शाला की मांग की गई है। उस बसाहट में निर्धारित योग्यता का व्यक्ति न होने पर उस ग्राम/ग्राम पंचायत से पहचान की जा सकती है। • गुरूजी के चयन में प्राथमिकता महिला को दी जायेगी। जहां एक से अधिक गुरूजी की आवश्यकता है। उनमें से एक अनिवार्य रूप से महिला होगी। • गुरूजी को स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ता माना जायेगा। • गुरूजी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी होगी। केवल महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल तक की छूट दी जायेगी। • डी.एड तथा बी.एड उपाधि धारकों को प्राथमिकता दी जायेगी। • ग्राम सभा एवं जिला ई.जी.एस. समिति के अनुमोदन उपरान्त पालक शिक्षक संघ एवं गुरूजी के मध्य अनुबंध पश्चात।
4	गुरूजी का मानदेय	• वर्ष 1997 – रू. 500/– प्रतिमाह • वर्ष 2001 – रू. 1000/–प्रतिमाह • वर्ष 2003 – रू. 2500/– प्रतिमाह (01.07.2001 से पूर्व अनुबंधित) • वर्ष 2003 – रू. 1000 – प्रतिमाह (01.07.2001 के पश्चात अनुबंधित) • वर्ष 2007 – रू. 2500/– प्रतिमाह (प्रौन्नत ई.जी.एस.) • वर्ष 2007 – रू. 1750/– प्रतिमाह (अप्रौन्नत ई.जी.एस.) • वर्ष 2008 – रू. 2500/– प्रतिमाह सभी को। • वर्ष 2012 – रू. 3600/– प्रतिमाह (20.09.12) सभी को।

5	शिक्षा गारंटी शाला का प्राथमिक शाला में उन्नयन	वर्ष 2001–02 – 22,659 प्रा.शा. में उन्नयन वर्ष 2004–05 – 3,868 प्रा.शा. में उन्नयन कुल – 26,527 ई.जी.एस. का प्रा. शा. में उन्नयन
6	गुरूजी पात्रता परीक्षा किसके लिए आयोजित की गई।	वर्तमान में कार्यरत गुरूजी/पर्यवेक्षक तथा औप. शिक्षा केन्द्र के तत्कालीन अनुदेशक तथा पर्यवेक्षकों हेतु आयोजित की गई।
7	गुरूजी पात्रता परीक्षा कब–कब आयोजित की गई।	प्रथम परीक्षा 31.08.2008 एवं द्वितीय परीक्षा 27.02.2011 को आयोजित की गई। प्रथम परीक्षा परिणाम 17.9.08 द्वितीय परीक्षा परि. 22.10.11
8	गुरूजी पात्रता परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया।	गुरूजी पात्रता परीक्षा में कुल 41284 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।
9	कुल कितने अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।	प्रथम पात्रता परीक्षा 2008 में 14645 एवं द्वितीय पात्रता परीक्षा 2009 (आयोजित 2011) में 13530 उत्तीर्ण हुए।
10	कितने अभ्यर्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए।	13109 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए।
11	गुरूजी पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अर्ह किस नियम के तहत किया गया।	मध्यप्रदेश पंचायत (संविदा शाला शिक्षक नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2005 के नियम 7 (क) के प्रावधान अनुसार किया गया।
12	क्या शासन द्वारा संविदा भर्ती नियम 2005 के संशोधित नियम 7 (क) के तहत कार्यपालिक आदेश जारी किये गये है।	म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ–44–56/2007/बीस–2 दिनांक14.05.10 द्वारा संविदा शाला श्रेणी–3 के पदों पर नियुक्ति हेतु पृथक से आयोजित पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार प्रावधान किया गया है– 1 अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पि.वर्ग तथा नि:शक्त व्यक्तियों सहित) के लिये 30 प्रतिशत एवं अन्य के लिये 40 प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए। 2 कमांक 01 के अतिरिक्त सकल रूप से आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पि.वर्ग तथा नि:शक्त व्यक्तियों सहित) के लिये 40 प्रतिशत अंक एवं अन्य के लिये 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होना चाहिये।
13	क्या गुरूजी पात्रता परीक्षा 2009 संशोधित परीक्षा परिणाम हेतु कार्यपालिक आदेश जारी किये गये है।	म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ–44/03/2012 दिनांक 24.01.12 द्वारा पूर्व में घोषित द्वितीय गुरूजी पात्रता परीक्षा का परीक्षा परिणाम को

(61) (111) (36) (74)

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 55-15/2012/20-2 भोपाल, दिनांक 18-5-2012

प्रति,

समस्त कलेक्टर,

मध्यप्रदेश

विषय - द्वितीय गुरूजी पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 के पद पर नियुक्ति दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ - स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ [illegible] दिनांक 24.01.2012

[illegible] संविदा शाला शिक्षक [illegible] 2012 के [illegible] के उपबंधों (4) में दिये गए प्रावधान के अनुसार [illegible] आदेश दिनांक 24.01.2012 द्वारा मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल [illegible] द्वितीय गुरूजी पात्रता परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों [illegible] मण्डल द्वारा अर्हित घोषित शाला शिक्षक श्रेणी-3 के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार [illegible]

1. शासन आदेश दिनांक 24.01.2012 के अनुसार [illegible] आयोजित द्वितीय गुरूजी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्राप्त [illegible] के प्रस्तुत [illegible] आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग व्यक्तियों सहित) के लिए 30 प्रतिशत [illegible] के लिए 49 प्रतिशत [illegible] प्राप्त किए हैं तथा जो विशेष प्रशिक्षण (डी.एड./बी.एड.) पाठ्यक्रम [illegible] प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 20 अंक [illegible] संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति करने की कार्यवाही की जाए।

2. [illegible]

3. शासन के आदेश क्रमांक एफ [illegible] दिनांक 14.06.2010 [illegible] मापदण्डों के अनुरूप द्वितीय गुरूजी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति के हकदार होंगे। (आदेश की प्रति संलग्न)

(35)
(112)
(62)

[illegible] पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों [illegible] पत्रों का परीक्षण जिला [illegible] समिति द्वारा किया जाएगा। उत्तीर्ण [illegible] अभ्यर्थियों से सकुशल [illegible] रूप में आवेदन प्राप्त किए जाएं। प्राप्त आवेदन [illegible] पृथक कर तीन भागों में [illegible] बांट ले तथा शेष बचे आवेदनों को अतिरिक्त [illegible] रखें।

[illegible] शिक्षा गारंटी शालाओं के कार्यरत गुरुजी।

[illegible] शिक्षा गारंटी शालाओं हेतु कार्यरत पर्यवेक्षक

[illegible] शासन के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा [illegible] अनुदेश।

[illegible] प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों का निम्न [illegible] किया जाना।

[illegible] शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र–उच्चतर [illegible] प्रमाण–पत्र [illegible]

[illegible] शैक्षणिक योग्यता की कोई उच्चतर माध्यमिक [illegible] परीक्षा [illegible]

[illegible] योग्यता परीक्षा की अंक सूची की मूल प्रति [illegible] अंक सूची [illegible]

[illegible] की पुष्टि संबंधित बोर्ड/कालेज से कराई जाए।

[illegible] आयु – नियुक्ति [illegible] रखने वाले [illegible] आयु [illegible]

[illegible] जन्मतिथि के प्रमाण [illegible] दसवीं [illegible] बोर्ड परीक्षा [illegible]

[illegible] मूल अंक सूची पेश की जाए।

[illegible] जाति प्रमाणपत्र [illegible]

[illegible] जाति प्रमाण पत्र [illegible] की जांच [illegible] परीक्षा परिणाम [illegible] जाति [illegible] के पश्चात [illegible] जाते [illegible] है तो उन्हें उत्तीर्ण अंक [illegible] द्वारा [illegible] होना चाहिए। इस प्रकार सामान्य वर्ग [illegible] आरक्षित वर्ग के उत्तीर्ण जाति [illegible] जनसूचित जनजाति [illegible] पिछड़ा तथा विशेष व्यक्ति [illegible] के अभ्यर्थी [illegible] प्रमाण करते [illegible] तो उनके लिए आवेदकों अंक [illegible] अनुसार [illegible] चाहिए।

[illegible] बुलाए गए अभ्यर्थियों [illegible] शैक्षणिक योग्यता [illegible] आयु [illegible] के सत्यापन के उपरान्त निम्नानुसार बिन्दुओं पर भी [illegible] पत्रों की जांच पृथक [illegible] निम्नानुसार की जाए –

[ ] शिक्षा गारंटी शालाओं के गुरूजियों हेतु :-

(1) नियुक्ति आदेश अथवा अनुबंध :- नियुक्ति आदेश की फोटो स्टेट, दिनांक रहित / शाला प्रबंधन समिति / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत के साथ जिला स्तरीय आदेश/अनुबंध की फोटो प्रति से मिलान करें। 01.01.1998 के बाद नियुक्त गुरूजियों के नाम की पुष्टि जिला एवं समिति की बैठक के कार्यवाई विवरण / बैठक के अभाव में उसके उपरान्त जारी निर्देश/आदेश / स्वीकृति से भी की जाए।

(2) नियुक्ति/अनुबंध दिनांक :- वर्तमान में कार्यरत ऐसे गुरूजी जो शपथ के पश्चात क्रमांक एफ 57-35, 2004 / 20-2 दिनांक 19.7.2005 के पूर्व की नियुक्ति हो।

(3) निरन्तरता :- नियुक्ति / अनुबंध की दिनांक से लगे दिनांक 19.07.2005 के पूर्व की हो तथा वर्तमान तक निर्बाध मानदेय प्राप्त किया हो, ऐसे गुरूजी ही नवेदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 में नियोजन के पात्र होंगे। शिक्षा गारंटी शालाओं में कार्यरत गुरूजी का चयन शिविर में उल्लेख सोपित किए गए है कि सेवा निरन्तरता की पुष्टि संबंधित विकासखण्ड / जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा मानदेय भुगतान हेतु मासिक उपस्थिति एवं मानदेय का सत्यापन पृथक से ही की जावे।

(4) न्यायालयीन विवाद :- गुरूजी की नियुक्ति अथवा बात न्यायालय में प्रचलित होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रखी जाएं।

(5) अनुशासनात्मक कार्यवाही :- अनुशासनात्मक कार्यवाही में दण्डित होने पर नियुक्ति नहीं की जाए। इसकी पुष्टि हेतु जिला परियोजना समन्वयक तथा संबंधित जनपद पंचायत / स्थानीय निकाय के मुख्यकार्यपालन अधिकारी दोनों से तदानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

(6) अन्य परिस्थितियाँ :- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर विशेष प्रकरण मानकर इसका निराकरण राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार किया जाए।

[ ] शिक्षा गारंटी शाला के पर्यवेक्षकों हेतु :-

(1) नियुक्ति आदेश :- नियुक्ति आदेश की मूल प्रति से मिलान करें।

(2) नियुक्ति दिनांक :- शिक्षा गारंटी शाला के पर्यवेक्षक के प्रकरण में जिला परियोजना कार्यालय (वर्तमान जिला शिक्षा केन्द्र) से अनुमोदन दिया जाता था, अतः नियुक्ति की पुष्टि जिला कार्यालय में उपलब्ध प्रति से तथा जनपद पंचायत के द्वारा जारी नियुक्ति आदेश से की जाएगी। यह किसी भी स्थिति में 31 दिसम्बर 2000 के बाद की नहीं होना चाहिए।

(3)

(114)

(64)

[illegible]

[illegible] नियमित/अनुबंध की दिनांक से जो कि [illegible] नियमित रूप से मानदेय प्राप्त किया हो एवं [illegible] नियोजन के पात्र होंगे। पर्यवेक्षक [illegible] उत्तीर्ण घोषित [illegible] कि सेवा निरन्तरता की पुष्टि संबंधित विकासखण्ड या केन्द्र/जिला [illegible] द्वारा मानदेय भुगतान हेतु मासिक उपस्थिति एवं मानदेय [illegible] के सत्यापन [illegible] की जावे।

(4) न्यायालयीन [illegible] :— पर्यवेक्षक की नियुक्ति संबंधी वाद न्यायालय में [illegible] की स्थिति में [illegible] न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रखी जाए

(5) अनुशासनात्मक कार्यवाही :— अनुशासनात्मक कार्यवाही में दण्डित होने पर नियुक्ति नहीं की जाए। [illegible] पुष्टि हेतु जिला परियोजना समन्वयक तथा संबंधित [illegible] पंचायत/[illegible] के मुख्यकार्यपालन अधिकारी दोनों से [illegible] प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

(6) अन्य परिस्थितियाँ :— उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर [illegible] प्रकरण मानक [illegible] निदेशक राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार [illegible]

(ग) औपचारिकेत्तर शिक्षा [illegible] के अनुदेशक/पर्यवेक्षकों हेतु :—

(1) नियुक्ति आदेश :— नियुक्ति आदेश की मूल-प्रति से मिलान करें।

(2) नियुक्ति दिनांक :— अनुदेशक व पर्यवेक्षक के प्रकरण में जारी नियुक्ति आदेश [illegible] की स्थिति में [illegible] 1999 के बाद की नहीं होना चाहिए।

(3) निरन्तरता :— [illegible] लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/पी.ए./[illegible]/2000 [illegible] दिनांक 22 अप्रैल 2000 तथा स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक [illegible] /2000 दिनांक 29 अगस्त 2000 के अनुक्रम में औपचारिकेत्तर शिक्षा [illegible] की तिथि भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न होने के कारण औपचारिकेत्तर [illegible] अनुदेशक तथा पर्यवेक्षकों की सेवा अवधि की निरन्तरता की [illegible] हेतु 31 [illegible] 2000 को अथवा 31 मार्च से 29 अगस्त, 2000 के मध्य को किसी भी [illegible] एक वर्ष पूर्व से [illegible] रूप से कार्यरत रहा हो तथा [illegible] आधार पर [illegible] अनुदेशक/पर्यवेक्षक की [illegible] पात्रता का निर्धारण किया जाए। चयन परीक्षा में उत्तीर्ण [illegible] अनुदेशक एवं पर्यवेक्षक की सेवा निरंतरता की पुष्टि DEO/BEO office पर संधारित अभिलेखों यथा [illegible] मानदेय भुगतान पंजिका/वेतनमान की [illegible] पुस्तक के आधार पर मानदेय की पुष्टि उपरान्त होनी चाहिए।

(65) (115)

[illegible]

[illegible] जिला स्तर पर [illegible] समिति कार्य करेगी

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत — अध्यक्ष
2. कलेक्टर का प्रतिनिधि — सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास / जिला संयोजक अदिमजाति कल्याण — सदस्य
5. प्राचार्य डाईट — सदस्य
6. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी — सदस्य
7. जिले का ओ.आई.सी. — विशेष आमंत्रित सदस्य
8. जिला परियोजना समन्वयक — सदस्य सचिव

6. बिन्दु क्रमांक 5 में उल्लेखित छानबीन समिति निम्न समय सारणी अनुसार इस संबंध में उल्लेखित गतिविधियों को समय-सीमा में सम्पन्न करेगी।

क्रमांक	गतिविधि	गतिविधि सम्पन्न करने की समय-सीमा		रिमार्क
		दिनांक से	दिनांक तक	
1	आवेदन पत्रों का छानबीन	06.06.12	15.06.12	
2	अंतिम सूची तैयार कर स्कूल पटल पर चस्पा करना	16.06.12		
3	अंतिम सूची पर अंतिम आपत्ति आमंत्रित करना	17.06.12	27.06.12	
4	आपत्तियों का निराकरण	28.06.12	07.07.12	
5	कलेक्टर से अंतिम सूची का अनुमोदन प्राप्त करना	08.07.12	09.07.12	अंतिम सूची जारी करने से पूर्व औपचारिकतर शिक्षा केन्द्र के अनुदेशक / पर्यवेक्षक के प्रकरणों में मौखिक सत्यापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6	अंतिम सूची जारी करना	10.07.12		

8. छानबीन समिति द्वारा तैयार अंतिम सूची पर सभी सदस्य हस्ताक्षर करेंगे एवं उनके द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि शासन आदेश की उपरोक्त कण्डिकाओं में उल्लेखित बिन्दुओं पर प्रत्येक आवेदक का परीक्षण किया गया है एवं अंतिम सूची शासन के मापदण्डों एवं निर्देशों के अनुरूप ही तैयार की गई है। अंतिम सूची की एक प्रति राज्य शिक्षा केन्द्र को

[illegible] कराये [illegible] प्रति शासन को भी [illegible]

[illegible] शिक्षक श्रेणी-3 के रूप में नियुक्त होने के उपरांत शिक्षा गारंटी शाला में [illegible] पर्यवेक्षक एवं म.प्र. शासन के तत्कालिन औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षक व अनुदेशकों को शासन द्वारा निर्धारित संविदा पारिश्रमिक राशि का भुगतान नियुक्ति दिनांक से किया जायेगा परन्तु अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के रूप में आवश्यक सेवा अवधि की गणना हेतु व्यापम द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि दिनांक 22.10.2018 से मान्य की जावेगी।

10. प्राथमिक शालाओं (पूर्व का शिक्षा गारंटी शालाएं) में कार्यरत गुरुजी व पर्यवेक्षक एवं म.प्र. शासन के तत्कालिन औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षक व अनुदेशकों के संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के रूप में नियुक्ति संबंधी प्रकरणों में कार्यवाही उपरोक्तानुसार की जाए।

(शोभा इनवाती)
उपसचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-15/2018/12-2 भोपाल, दिनांक 18-5-22

प्रतिलिपि-

1. सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन
2. विशेष सहायक, मा. मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल।
8. आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल।
9. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
14. समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास, मध्यप्रदेश।
15. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
16. http://www.sse.mp.gov.in/Circular/educationportal में अपलोड करने हेतु।

अग्रेषित।

उपसचिव
स्कूल शिक्षा

(67) (117) (40)

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 10.02.2014

क्रमांक एफ–44–6/2014/20–2 : राज्य शासन एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. पंचायत शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2005 के नियमों में नियम–7 'क' में उपनियम–(3), (4) तथा (5) स्थान पर संशोधन दिनांक 28 दिसम्बर 2013 को अधिसूचना अनुसार निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाऐ, अर्थात्:–

"(3) ऐसे गुरूजीं एवं पर्यवेक्षक जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, संविदा शाला शिक्षक वर्ग–3 के पद पर परीक्षा लिए बिना, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी की सरकार द्वारा अवधारित की जाए, नियोजित किए जा सकेंगे।

(4) ऐसे गुरूजी एवं पर्यवेक्षकों का, जो मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2005 में विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों, ऐसे नियोजन के तीन वर्ष पश्चात् इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन किया जा सकेगा कि उन्हें संविदा शाला शिक्षक वर्ग–3 के पद पर नियोजन की तरीख से तीन वर्ष के भीतर डी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा'

मध्यप्रदेश पंचायत शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2005 के नियमों में नियम–7 'क' में उप नियम–(3), (4) तथा (5) स्थान पर संशोधन दिनांक 28 दिसम्बर 2013 के तहत कार्यवाही की जावे।

2. ऐसे गुरूजी एवं पर्यवेक्षक जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के पद पर, परीक्षा लिए बिना, नियोजन किये जाने हेतु म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देश–म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ–44–14/03/2012/20–2 दिनांक 18.05.12 के अनुसार नियोजन की कार्यवाही निम्नानुसार की जावे।

3. **शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र**:–उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा अथवा समकक्ष न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जांच उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा अथवा समकक्ष न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की अंकसूची की मूलप्रति से करें। डूप्लीकेट अंकसूची/प्रमाण–पत्र होने पर उसकी पुष्टि संबंधित बोर्ड/मण्डल से कराई जाये।

4. **आयु**:–नियुक्ति हेतु अर्हता रखने वाले गुरूजी एवं पर्यवेक्षक की अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक न हो। जंन्मतिथि के प्रमाण हेतु कक्षा 10वीं/11वीं जो भी बोर्ड परीक्षा रही हो, की मूल अंकसूची मान्य की जाये।

(अ) शिक्षा गारंटी शाला के गुरूजियों हेतु:–

(1) **नियुक्ति आदेश अथवा अनुबंधः–** नियुक्ति आदेश या पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के साथ किये गये आदेश/अनुबंध की मूल प्रति से मिलान करें। 01.01.1998 के बाद नियुक्ति गुरूजियो के नाम की पुष्टि जिला ई.जी.एस. समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण/बैठक के आधार पर उसके उपरान्त जारी निर्देश/आदेश/स्वीकृति से भी की जाए।

(2) **नियुक्ति/अनुबंध दिनांकः–** वर्तमान में कार्यरत् ऐसे गुरूजी जो शासन के पत्र क्रमांक एफ–57–36/2004/20–2 दिनांक 19.07.2005 के पूर्व से नियुक्त हो।

(3) **निरन्तरताः–** नियुक्ति/अनुबंध की दिनांक से जो कि 19.07.2005 के पूर्व की हो से वर्तमान तक नियमित मानदेय प्राप्त किया हो, ऐसे गुरूजी ही संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 में नियोजन के पात्र होगें। शिक्षा गारंटी शालाओं में कार्यरत् गुरूजी कि सेवा निरन्तरता की पुष्टि संबंधित विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा मानदेय भुगतान हेतु मासिक उपस्थिति एवं मानदेय के सत्यापन पत्रक से ही की जावे।

(4) **न्यायालयीन विवादः–**गुरूजी की नियुक्ति संबंधी वाद न्यायालय में प्रचलित होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के अधीन रखी जाए।

(5) **अनुशासनात्मक कार्यवाहीः–**अनुशासनात्मक कार्यवाही में दण्डित होने पर नियुक्ति नही की जाए। इसकी पुष्टि हेतु जिला परियोजना समन्वयक तथा संबंधित जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय के मुख्यकार्यपालन अधिकारी दोनों से तदानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

(6) **अन्य परिस्थितियाँः–**उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ उदभूत होने पर विशेष प्रकरण मानकर इसका निराकरण राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार किया जाए।

ब. शिक्षा गारंटी शाला के पर्यवेक्षकों हेतुः–

(1.) **नियुक्ति आदेशः–**नियुक्ति आदेश की मूल प्रति से मिलान करें।

(2.) **नियुक्ति दिनांकः–**शिक्षा गारंटी शाला के पर्यवेक्षक के प्रकरण में जिला परियोजना कार्यालय (वर्तमान जिला शिक्षा केन्द्र) से अनुमोदन दिया जाता था, अतः नियुक्ति की पुष्टि जिला कार्यालय में उपलब्ध प्रति से तथा जनपद पंचायत के द्वारा जारी नियुक्ति आदेश से की जायेगी। यह किसी भी स्थिति में 31 दिसम्बर 2000 के बाद की नही होनी चाहिए।

3.) **निरन्तरताः–**नियुक्ति/अनुबंध की दिनांक से जो कि 31 दिसम्बर 2000 के पूर्व की हो, वर्तमान तक नियमित रूप से मानदेय प्राप्त किया हो, ऐसे पर्यवेक्षक ही संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 में नियोजन के पात्र होंगे। पर्यवेक्षक की सेवा निरन्तरता की पुष्टि

संबंधित विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा मानदेय भुगतान हेतु मासिक उपस्थिति एवं मानदेय भुगतान के सत्यापन पत्रक से की जावे।

) न्यायालयीन विवादः—पर्यवेक्षक की नियुक्ति संबंधी वाद न्यायालय में प्रचलित होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रखी जाये।

(5.) अनुशासनात्मक कार्यवाहीः—अनुशासनात्मक कार्यवाही में दण्डित होने पर नियुक्ति नही की जाए। इसकी पुष्टि हेतु जिला परियोजना समन्वयक तथा संबंधित जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोनों से तदानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

(6.) अन्य परिस्थितियाँः—उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ उद्भूत होने पर विशेष प्रकरण मानकर इसका निराकरण राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार किया जाए।

5. जिला स्तरीय छानबीन समितिः—

उक्त कार्य को संपादित करने के लिए जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति कार्य करेगी—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत — अध्यक्ष
2. कलेक्टर का प्रतिनिधि — सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/ जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण — सदस्य
5. प्राचार्य डाइट — सदस्य
6. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी — सदस्य
7. जिले का ओ.आई.सी. — विशेष आमंत्रित सदस्य
8. जिला परियोजना समन्वयक — सदस्य सचिव

6. बिन्दु क्रमांक—3 में उल्लेखित छानबीन समिति द्वारा तैयार अनंतिम सूची तैयार कर सूचना पटल पर चस्पा करना एवं अनंतिम सूची पर आपत्तियाँ आमंत्रित करना, तथा आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा। कलेक्टर से अंतिम सूची पर अनुमोदन प्राप्त कर अंतिम सूची जारी की जाये।

7. जिला छानबीन समिति द्वारा तैयार अंतिम सूची पर सभी सदस्य हस्ताक्षर करेंगे एवं उनके द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि **"शासन आदेश की उपरोक्त कण्डिकाओं में उल्लेखित बिन्दुओं पर प्रत्येक गुरूजी एवं पर्यवेक्षक का परीक्षण किया गया है, एवं अंतिम सूची शासन के मापदण्डो एवं निर्देशों के अनुरूप ही तैयार की गई है।"** अंतिम सूची की एक प्रति राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराई जाये। इस सूची पर जिला कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये। अनुमोदन उपरान्त अंतिम चयन सूची संबंधित जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को विहित

प्रकिया एवं निर्देशानुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के पद पर नियोजन हेतु उपलब्ध कराई जायें, जिसकी प्रति शासन को भी पृष्ठांकित की जाये।

3. संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रूप में नियोजित होने के उपरान्त शिक्षा गारंटी शाला में कार्यरत् गुरूजी व पर्यवेक्षक को शासन द्वारा निर्धारित संविदा पारिश्रमिक राशि का भुगतान नियुक्ति दिनांक से किया जायेगा।

4. प्राथमिक शालाओं (पूर्व की शिक्षा गारंटी शालाएं) में वर्तमान में कार्यरत् गुरूजी एवं पर्यवेक्षक के संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रूप में नियोजन संबंधी कार्यवाही उपरोक्तानुसार की जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

10.2.14

(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 10.02.2014

क्रमांक एफ–44–6/2014/20–2
प्रतिलिपि–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल।
8. आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल।
9. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
14. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
15. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
16. एजूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11.2.14

उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 9/2/14

क्रमांक एफ 44–6/2014/20–2:: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10.2.2014 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार अनुपूरक निर्देश जारी करता है:–

1. ऐसे गुरूजी एवं पर्यवेक्षक जो म.प्र. शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत थे, को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रूप में नियोजित होने की तिथि से शासन द्वारा निर्धारित संविदा पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जायेगा।
2. अध्यापक संवर्ग में संविलियन किये जाने हेतु आवश्यक सेवाकाल की गणना विभागीय आदेश जारी दिनांक 10.2.14 से की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कलावती उइके)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 44–6/2014/20–2
भोपाल, दिनांक 9/2/14

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
2. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव,म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
5. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग,मंत्रालय भोपाल
6. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास विभाग भोपाल
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश
11. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12. आर्डर बुक

अवर सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

::राकेश मुले::

(72) (123)

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

भोपाल, दिनांक 27/09/2018

:: आदेश ::

एफ 1–3/2017/20–1:: विभागीय आदेश क्रमांक 44–6/2014/20–2 दिनांक 10.02.2014, ऐसे गुरूजी एवं पर्यवेक्षक जो तत्समय मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत थे, को संविदा शाला शिक्षक 3 के पद पर परीक्षा लिए बिना नियोजित करने के संबंध में जारी किया गया। उक्त आदेश में यह भी लेख किया गया था कि उनके नियोजन की कार्यवाही विभागीय आदेश दिनांक 18.05.2012 के अनुसार किस प्रकार की जाए।

2/ विभागीय आदेश क्रमांक 44–6/2014/20–2 दिनांक 09.12.2014 [illegible] आदेश दिनांक 10.02.2014 के अनुक्रम में जारी किया गया जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त गुरूजी एवं पर्यवेक्षकों को अध्यापक संवर्ग में संविलियन किए जाने हेतु आवश्यक सेवा काल की गणना विभागीय आदेश जारी करने के दिनांक अर्थात 10.02.2014 से की जाएगी।

3/ उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44–14/2012/20–2 दिनांक 18.05.2012 अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण गुरूजी एवं पर्यवेक्षकों के संबंध में है, जबकि विभागीय आदेश क्रमांक 44–6/2014/20–2 दिनांक 10.02.2014 अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले गुरूजी एवं पर्यवेक्षकों के संबंध में है।

4/ इस संबंध में पुनः स्थिति स्पष्ट की जाती है कि अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले गुरूजी एवं पर्यवेक्षकों की वरिष्ठता किसी भी स्थिति में दिनांक 10.02.2014 से पूर्व की तिथि से प्रदान नहीं की जा सकती जैसाकि विभागीय आदेश दिनांक 09.12.2014 द्वारा आदेशित किया गया है। अतः अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले गुरूजियों एवं पर्यवेक्षकों की वरीष्ठता विभागीय आदेश दिनांक 09.12.2014 द्वारा आदेशित अनुसार दिनांक 10.02.2014 से मान्य की जावे।

उपर्युक्तानुसार स्पष्टीकरण से भिन्न स्थिति मान्य करते हुए यदि किन्हीं अधीनस्थ कार्यालय द्वारा किन्हीं अभ्यार्थियों को अन्यथा लाभ दे दिया गया है तो ऐसे आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। इस संबंध में कार्यवाही न करने की स्थिति में संबंधित त्रुटिकर्ता अधिकारी की जबावदारी नियत की जाकर उनसे आवश्यक वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
27/09/18
(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 27/09/2018

पृ.क्र. एफ 1–3/2017/20–1
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र., भोपाल। कि
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/विधि प्रकोष्ट, लोक शिक्षण, म.प्र.।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7. आर्डर बुक।

27.09.18
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

D.S.P. 187 27.9.18

Dated 2122 27/9/18 DDCS.(R)

22.09.18